1191
01/02/16

खण्ड-12 संख्या-12

एकादश

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

भाग- 2

कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित

सोमवार, तिथि 13 जुलाई 1998 ई०

इसमें सर्वश्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह, राधाकृष्ण किशोर, अश्विनी कुमार चौवे, प्रेम कुमार, वृशिण पटेल का कटौती का प्रस्ताव है, क्रमांक २२१ से २२५ । माननीय सदस्य, श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह, कटौती का प्रस्ताव मूभ करें ।

(इस अवसर कांग्रेस पार्टी के बहुत से माननीय सदस्य सदन के वेल में चले आये)

कटौती प्रस्ताव : राज्य सरकार की ऊर्जा की नीति पर विचार-विमर्श (अस्वीकृत)

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"इस वीर्षक की मांग १०/- रु० से घटायी जाए"

राज्य सरकार की ऊर्जा विभाग की नीति पर विचार विमर्श करने के लिए ।

उपाध्यक्ष : झारखंड के मसले पर सरकार ने उत्तर दिया, बाद में जब आपने उठाया तो फिर सरकार ने कहा कि संमीक्षा करेंगे ।

(सदन में शोरगुल)

उपाध्यक्ष : अपनी सीट से यहां आने की क्या जरूरत है, आपलोग अपने अपने आसन पर जाईये । यह सवाल उस समय भी उठा था, उस समय आपलोग हाऊस में नहीं थे ? आप उस समय कहां थे ? अब आज आसम पर जाईये । आसन पर जाईये और जो कुछ बोलना है, वहां से बोलिये ।

(शोरगुल)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य सदन के वेल से अपनी-अपनी जगह पर चले गये)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : अभी आपलोग आम्सन ग्रहण करें, अभी सरकार से.........

श्री अबध बिहारी सिंह(महगामा) : पहले हमलोगों की बात सुन ली जाय ।.

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बात प्रात: कॉल अटेंशन के समय उठी थी ।

श्री सुशील कुमार मोदी : चूंकि सरकार ने कहा था, इस पर ध्यानाकर्षण नहीं था उपाध्यक्ष महोदय । सरकार में, माननीय श्री तुलसी सिंह, मंत्री बैठे हुये हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आज का आप कार्य-सूची देख लीजिये ।

श्री सुशील कुमार मोदी : सरकार अपने से खडे होकर उत्तर दिया ....

उपाध्यक्ष : आज ध्यानाकर्षण था ।

श्री सुशील कुमार मोदी : यह किनका ध्यानाकर्षण था ?

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रशान्त कुमार का था । मैं सरकार से प्रस्ताव करता हूँ कि वे स्पष्टीकरण दें ।

(व्यवधान)

श्री अवध बिहारी सिंह : पहले हमलोगों की बात सुन ली जाय ।

श्री फुरकान अंसरी : आसन से बात हुई थी एडजार्नमेंट मोशन के समय कि इनकी बात सुन ली जाय । इस पर सरकार का हुआ था कि आपलोगों की भावना से अवगत होकर, आप लोगों से बातें करके जबाब देंगे, लेकिन आज जो जबाब हुआ है, इससे पहले हमलोगों से बातें होनी चाहिये थी, सरकार हमलोगों का बिना सहयोग लिये, राय-विमर्श किये हुये आज जबाब हुआ है, इस बात की आपत्ति है । दूसरी बात संथालपरगना-छोटानागपुर ऑटोनोमस कांसिल बना है, उस क्षेत्र के गरीबों के विकास के लिये, विकास का कोई काम "जैक" नहीं कर रहा है, वह सिर्फ ट्रांसफर-पोस्टींग कर रह है, एक ब्लौक में २-२ बी0डी0ओ0, ३-३ सी0 ओ0 की पोस्टींग हो रही है, जितनी नदियां है उस क्षेत्र में, उनमें पुलों का फाउन्डेशन, शिलान्यास कर रहे हैं, उस इलाका में धोखा देने

के अलावा वहां के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष : आप भाषण दीजियेगा ? आप क्या रखना चाहते हैं ? आप विधान-सभा को मजाक बना दिये हैं ।

श्री फुरकान अंसारी : जैक के नियम में "जैक" को ट्रांसफर, पोस्टींग करने का कोई अधिकार नहीं हैं, इसलिये इनकी सेवा उस इलाके में सौपी नहीं जा चुकी है ।

उपाध्यक्ष : नई बिन्दु, नई बात आप क्या रख रहे हैं ?

श्री फुरकान अंसारी : इन लोगों के वेतन पर रोक लगा दी गई है, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमलोगों से राय-विमर्श लेकर ही कुछ बात करे सरकार ।

श्री सुशील कुमार मोदी : जो विषय माननीय सदस्य श्री फुरकान अंसारी ने उठाया है, यह बहुत गंभीर मामला है । बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या- सी0एम0 ३-१०१६/८०-३९१८ दिनांक २५ अक्टूबर, १९८०, यह बिहार सरकार के गजट में प्रकाशित है जिसके तहत राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण का अधिकार स्थापना समिति, जो प्रत्येक विभाग में बनती है उसका अधिकार है, उस स्थापना समिति का गजट में अधिसूचना होती है । बिहार सरकार ने "जैक" के अन्तर्गत स्थापना समिति का गठन ही किया है और न अधिकृत ही किया है स्थानान्तरण के लिये- इसके बाबजूद १५० बी0डी0ओ0 / सी0ओ0, अन्य ऑफिसर, ब्लौक हेल्थ ऑफिसर, सप्लाई ऑफिसर की एक जगह पर २-३ की पोस्टींग की है, उसका प्रमाण यह है कि जिनका "जैक" के द्वारा ट्रांसफर हुआ, उनको पे-स्लीप नहीं मिला है, वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको ऊपर की आमदनी इतनी हो रही है कि उन्हें पे-स्लीप की कोई परवाह नहीं है । पूरे झारखण्ड क्षेत्र में आज घोर अराजकता की स्थिति हो गई है । माननीय मंत्री श्री तुलसी सिंह का अखबार में तीन बयान आया कि "जैक" को अधिकार नहीं स्थानान्तरण करने का फिर राज्य सरकार ने क्यों इस प्रकार से एक जगह पर २-२, ३-३ बी0डी0ओ0 - और यह गंभीर आरोप लगा है "जैक" के लोगों पर

कि एक-एक लाख, ५०-५० हजार रु० लेकर स्थानान्तरण इन्होंने किया है- यह गंभीर आरोप है "जैक" के अधिकारियों पर । ऐसी स्थिति में सरकार स्पष्ट नहीं करेगी, पूरे झारखंड क्षेत्र में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है । अगर "जैक" को अधिकार देते हैं तो दीजिये, इसके लिये इनका गजट नाटिफिकेशन कीजिये ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायं । एक ही बिन्दु पर कितना बोलेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, नेता, विरोधी दल ने जो बातें रखी हैं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन्होंने जो बातें कि पैसा लेकर किया गया है उसको कार्यवाही से हटा दिया जाय ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप बैठ जायं । मंत्री जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं ।

श्री अवध बिहारी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि झारखंड अटोनोमस काउंसिल के बारे में बातें चल रही हैं । महोदय, आप जानते हैं कि झारखंड अटोनोमस काउंसिल है । एक गवर्नमेंट होता है ओर एक काउंसिल होता है । सरकार का एक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है और एक एक्ट के तहत होता है । महोदय, झारखंड अटोनोमस काउंसिल का सरकार ने जो सृजन किया है उसके संबंध में मंत्री जब जबाब देंगे तो मेरे सवाल का भी जबाब देंगे कि झारखंड अटोनोमस काउंसिल एक्जीक्यूटिव आर्डर से चलाना चाहते हैं कि एल0एस0जी0 से चलाना चाहते हैं ? एल0एस0जी0 एक्ट पुराना गवर्नमेंट का होता हे और उसमें काउंसिल के अधिकार होते हैं । विरोधी दल के नेता ने दुरूस्त कहा है कि काउंसिल को ट्रांसफर पोस्टिंग का पावर होता है। वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड बना था तो वहां की सरकार ने यही पावर दिया और क्या पावर दिया माननीय नेता दिख रहे थे । राजपत्रित पदा0 का तबादला होता

है तो ऑर्डर में लिखा रहता है बाई दी ऑर्डर ऑफ गवर्नर । झारखंड अटोनोमस काउंसिल को यहां जो पावर दिया गया है वह एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से दिया गया है बाई द ऑर्डर ऑफ गर्वनर ही दिया गया है ? एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से दिया है ता उसको स्थापना का पावर है । रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव विजनेस में स्थापना का पावर होता है । लेकिन एक राज्य में दो गर्वनमेंट काम करेगी ? गवर्नमेंट एक ही होती है ।

उपाध्यक्ष : हो गया न ? बैठिये ।

श्री अवध बिहारी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और । गवर्नमेंट एक ही होती है । सरकार ने झारखंड अटोनोमस काउंसिल बनाया है डेवलपमेंट करने के लिये । ट्रांसफर पोस्टींग के लिये थोड़ा बहुत पावर दिया है । माननीय सदस्य, श्री फुरकान अंसारी कहते हैं कि डेवलपमेंट करता नहीं केवल ट्रांसफर पोस्टींग का एक इंडस्ट्री लगा रखा है । क्या सरकार इस पर कंट्रोल करेगी ? एक-एक ब्लौक में दो दो, तीन तीन बी0डी0ओ0 रखे गये हैं, काम होता नहीं है । ट्रासंफर पोस्टींग जैक कर देता है ए0जी0 मानते नहीं हैं । डिस्ट्रीक्ट मैजिस्ट्रेट के प्रेसर से वे पदाधिकारी ज्वाइन कर लेते हैं । इसलिये महोदय, सरकार की क्लीयर कट मंशा होनी चाहिये कि वह क्या चाहती है ? सरकार स्पष्ट करें क्योंकि एक्जीक्यूटिव आर्डर का कोई लिमिटेशन होता है । बिना कानून की सरकार है कि सरकार कानून से चलेगा ? इसलिये सरकार स्पष्ट करे कि एक्जीक्यूटिव आर्डर से चलता है कि एल0एस0जी0 ऐक्ट से चल रहा है?

श्री स्टीफेन मराण्डी : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो झारखण्ड एरिया औटोनौमस का ऐक्ट बना है वह इस सदन से पारित है । ऐक्ट में बहुत स्पष्ट है कि । अधिनियम के 32(क) में गजटेड अफसर के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जैक को दिया है और महोदय, वहां कोई फंगशनिंग नहीं होता है, उसके फंगशंस के लिए रूल्स बने हुए हैं और उसी के तहत तीन वर्ष के लिए सेवा सुपुर्द है । उपाध्यक्ष महोदय, अभी नेता विरोधी दल ने कहा है कि वहाॅ इशटैब्लिशमेंट कमिटी नहीं बनी है, मैं आपको सदन को

बतलाना चाहता हूं ....

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : इन्हीं के गलत कारनामों के चलते यह समस्या उठ रही है, जो बात ये उठा रहे हैं उसको गवर्नमेंट अपने जबाब में कहेगी या इनसे ही कहलाईयेगा ।

श्री स्टीफेन मराण्डी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जितना भी स्थानान्तरण हुआ है उसके खिलाफ में कई पदाधिकारी माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं और उसका ऑर्डर भी है और इन सब का केस खारिज हुआ है । माननीय उच्च न्यायालय ने बतलाया है कि ऐक्ट में प्रवधान है, वह अगर जैक करता है तो मान्य है, यह कोर्ट का आदेश वहाँ हुआ है और ये बोल रहे हैं कि पे-स्लिप नहीं मिल रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, जितने पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है उनलोगों को पे-स्लिप मिल रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए यह जो नेता विराधी दल कहते हैं कि इनको अधिकार नहीं है । ऐक्ट के तहत कार्य हो रहा है और कोर्ट ने भी मान्यता दी है और पे-स्लिप दिया जा रहा है ।

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना है......

उपाध्यक्ष : महेन्द्र सिंह जी मा0 मंत्री का उत्तर हो जाने दीजिये ।

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह : इनलोगों ने जो बात बतलायी उसमें आगे बात यह है कि राज्य सरकार उन संबंधित पदाधिकारियों की सेवा सौपेंगी और मैं कह रहा हूं कि सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए एकरारनामा किया । बिल भी लाए हैं लेकिन उस बिल में कानूनी प्रौब्लेम हुआ, यह परिषद में गिर गया और सरकार दुबारे असेम्बली में लायी नहीं इसलिए सेवा शर्त्त को सौंपा भी नहीं - यह सारी अराजकता राज्य सरकार की अवसरवादी तौर तरीकों के कारण है । इसका कारण यह है कि एक एक प्रखण्ड में अनेक अंचलाधिकारी हैं, अनेक बी0डी0ओ0 हैं, अनेक जिला शिक्षा अधीक्षक हैं आज पूरा राज्य अराजकता का पर्याय बन गया है । हम आसन से आग्रह करेंगें कि सरकार इस अराजकता को अबिलम्ब खत्म करे और उसके लिए जो जिम्मेदार हैं वे अपनी गलती कबूल करें ।

श्री तुलसी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले माननीय सदस्यों को और सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि ध्यानाकर्षण के तहत एक खास दफा 32(2) के तहत ध्यानाकर्षण किया गया है और उसका जबाब भी दिया जा चुका है, और उस वक्त कोई मेम्बर उपस्थित नहीं हों, तो रिओपेन नहीं किया जा सकता है लेकिन जनहित की दृष्टि से आपने क्या किया, आपने कहा कि इसको फिर से बतला दीजिये, माननीय सदस्यों को बतला दीजिये । कांग्रेस के माननीय नेता से मैंने बातचीत की, दूरभाष से फुरकान अंसारी से भी बातचीत की है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे साफ-साफ कहना चाहता हूं कि जो झारखण्ड अधिनियम पारित हुआ है वह सभी दलों के सदस्यों की राय से पारित हुआ है और यह जो ध्यानाकर्षण सूचना है उसी अधिनियम के 32(2) के तहत है इसलिए स्पष्ट सरकार ने कहा है । उसको मैं पुनः पढ़ देता हूं । "झारखण्ड स्वशासी परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 32(2) के मुताबिक विनिर्दिष्ट विभागों को पूर्णतः संबंधित राजपत्रित अधिकारियों की सेवा राज्य सरकार द्वारा परिषद् को सौंपे जाने पर स्थानान्तरण और पदस्थापना संबंधी राज्य सरकार की नीति के मुताविक उस क्षेत्र में स्थानान्तरण और पदस्थापन करने का अधिकार झारखण्ड स्वशासी परिषद् को है ।"

दूसरा, विनिर्दिष्ट विषयों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, 3-4 विभागों का नाम लिया था ।

विनिर्दिष्ट बिषयों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, प्राथमिक एवं प्लस टू तक की माध्यमिक शिक्षा, ग्रामीण विकास आते हैं । जहाँ तक राजस्व विभाग का प्रश्न है, सरकार और जैक के बीच जुलाई 97 में हुए समझौते के मुताबिक राजस्व विभाग के अधीन अंचलाधिकारियों की सेवाएँ भी परिषद् को सौंपना है। कल्याण विभाग में 30 जून 98 में कोई स्थानान्तरण प्रदस्थापना नहीं हुआ है । सरकार इस बात पर कटिबद्ध है कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद् अधिनियम और सरकार और झारखंड क्षेत्र स्वाशासी परिषद् के बीच हुए समझौता का पालन हो । जून 30 को विभिन्न विभागों द्वारा किए गए स्थानान्तरणों पर सरकार अलग से बैठक करके इसका समाधान निकालेगी ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, जब ऐक्ट ही कॉसिल में गिर गया, जब गवर्नर का दस्तखत नहीं हुआ तो फिर क्या विचार होगा ।

श्री तुलसी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह वाद-विवाद का विषय नहीं है, यह ध्यानाकर्षण है, ध्यानाकर्षण में जो विषय है, उससे आप बिषयांतर नहीं हो सकते हैं । पहले आप मेरी बात को सुनिये । यह बिषय बहस का नहीं है, अगर बहस होती है, जो बिन्दु उठते हैं, सरकार उसका जबाब देगी । आम ध्यानाकर्षण ....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, जब ऐक्ट विधान-परिषद् में गिर गया और अभी तक उस हाउस में दोबारा नहीं लाया गया, गवर्नर का उसपर दस्तखत नहीं हुआ तो ऐक्ट मैलिड कहाॅ रह गया ?

श्री तुलसी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्री रघुनाथ झा जी चार, पाॅच महीना पहले इसी कुर्सी पर बैठते थे और इसी पर आपने कितना बार जबाब दिया है। महोदय, सोये हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो जान-बूझकर सोया हुआ हो, उसको जगाना मुश्किल है । झा जी, जान बूझकर सोये हुए हैं, इसलिए उनको नहीं जगाया जा सकता है । महोदय, उन्होंने कहा कि जो ऐक्ट है, उस ऐक्ट के तहत ....

(व्यवधान)

आप सुनते नहीं हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जो ध्यानाकर्षण में प्रश्न उठा है, उसका हम जबाब दे रहे हैं । इसमें है कि विधान-सभा से पारित ऐक्ट की धारा 32(2) के अन्तर्गत झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद् को दिए गए विषयों पर स्थानान्तरण, पदस्थापन की दोहरी नीति अख्तियार की गई है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 30 जून के पदस्थापन के बारे में...............

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बहुत सारे माननीय सदस्यों का एक तरह का ही प्रश्न है कि यदि आप उत्तर को स्वीकार कर रहे हैं कि ऐक्ट के मुताबिक अधिकार है तो फिर राज्य सरकार ने क्यों वहाँ पोस्टिंग कर दिया ?

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : असल में उपाध्यक्ष महोदय, यही हो रहा है । अलग से यहाँ से हो रहा है और वहाँ से भी अलग से नोटिफिकेशन हो रहा है । डी0ई0ओ0 जो क्लास वन ऑफिसर हैं, कार्यपालक अभियंता का, सहायक अभियंता का स्थानान्तरण वहाँ से हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री तुलसी सिंह : महोदय, ध्यानाकर्षण में है कि 30 जून की तारीख में बिहार सरकार के द्वारा बदली कर दी गयी है, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि 30 जून 98 को कल्याण विभाग में कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ है । सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद् और राज्य सरकार के साथ समझौता का पालन हो । महोदय, 30 जून 98 को किये गये स्थानान्तरण पर सरकार अलग से बैठक करेगी और इसका समाधान निकालेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई नयी चीज आती है, उसमें थोड़ा व्यवधान तो आता ही है ।

(व्यवधान)

पहले मेरी बात को सुन लीजिये । माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण किया है, उसमें कहा है कि 30 जून के आदेश से गड़बड़ी पैदा हुई है । सरकार अलग से इसपर विचार करेगी और उसका समाधान निकालेगी ।

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : महोदय, यह गड़बड़ी हुई है, सरकार के आदेश से।

माननीय मंत्री, तुलसी बाबू जो कह रहे हैं, अगर वही सत्य है तो ऐसा किया जाये कि गवर्नमेंट झारखंड क्षेत्र.............

(व्यवधान)

अपनी बात छोड़िये, मेरी बात सुन लीजिए । उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कहा, हमलोग मान लेते हैं जबतक हमलोगों से बात नहीं कर लेते हैं तबतक वह रूका रहेगा ।

श्री तुलसी सिंह : हुजूर, मैं फिर कहना चाहता हूं कि अलग से विचार करके इसका समाधान निकाला जायेगा ।

श्री सुशील कुमार मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह "जैक" का अधिकार है । मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि छः जुलाई, 1998 को 36 बी0डी0ओ0 का स्थानान्तरण आदेश ग्रामीण विकास विभाग ने कैसे निकाला मंत्री महोदय, या तो आदेश बिहार सरकार का हो या जैक का हो, दोनों का कैसे होगा ?

श्री तुलसी सिंह : इस पर बहस करवाइये ।

श्री सुशील कुमार मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, 6 जुलाई, 1998 को 36 बी0डी0ओ0 का स्थानान्तरण क्या ग्रामीण विकास विभाग, पटना ने नहीं किया है ?

उपाध्यक्ष : स्वीकार तो कर ही रहे हैं ।

श्री सुशील कुमार मोदी : "जैक" या बिहार सरकार के आदेश से स्थानान्तरण होगा ?

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी सदन को अवगत कराया कि सरकार से गड़बड़ी हुई है ।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने सदन को

अवगत कराया कि 30 जून के दौरान सरकार का जो आदेश हुआ, उसमें गड़बड़ी हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि उस गड़बड़ी के लिए सरकार ने किसी को शिनाख्त किया कि कौन जिम्मेवार है और उसके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री तुलसी सिंह : महोदय, जो सूचना मिली है, उसके आधार पर 30 जून के सवाल पर जो जबाब मांग गया है, सरकार अलग से विचार कर समाधान निकालेगी, विचार करेगी।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : "जैक" द्वारा आदेश किया गया है इन्होंने कहा तो जबतक आप हमलोग से बात नहीं करते हैं तबतक सारी कार्रवाई स्थागित कीजिए।

उपाध्यक्ष : स्थगित करने का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बैठिये। मैं आग्रह कर रहा हूं। यह सवाल 8 जुलाई, 1998 को रामाश्रय बाबू ने सदन के समक्ष लाया था। 9 जुलाई को माननीय सदस्य प्रशांत जी के तरफ से एडजॉर्नमेंट मोशन आया। उस समय रामाशश्रय बाबू ने प्वायंट आऊट किया कि मैंने एक दिन पूर्व ही इसको उठाया था जिसका उत्तर सरकार ने 13 जुलाई को दिया कि एक समीक्षा करके समाधान निकालेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : मेरा कहना है कि यह सूचना सदन के माध्यम से 8 तारीख को ही सरकार के पास पहुंच गया और आज ध्यानाकर्षण के उत्तर के क्रम में सरकार ने समीक्षा की बात कही है और कोई समय-सीमा भी नहीं तय की है जबकि सदन चल रहा है इस प्रकार पदस्थापन और स्थानान्तरण के संबंध में कौअस और एनारकी बरकरार है। यह सरकार के लिए अच्छी सूचना नहीं है। इसके समाधान के लिए सरकार कोई समय सीमा तय कर उत्तर दे।

(व्यवधान)

श्री तुलसी सिंह : महोदय, एक सूचना है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : एक समय-सीमा तय कर दीजिए । बैठिये, बैठिये । सरकार ज़बाब दे रही है ।

श्री तुलसी सिंह : महोदय, आसन का जो आदेश है उस संबंध में मेरा ऐसा नहीं कहना है कि समीक्षा हो रहा है, मेरा कहना है कि जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, उसको देख लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिए ।

श्री सुशील कुमार मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अध्यक्ष महोदय अपने चेम्बर में सभी दल के नेताओं को और माननीय मंत्री जी को बुलाकर इसका समाधान निकालें कि इसका क्या समाधान होगा ।

महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि "जैक" को अधिकार है । लेकिन 6 जुलाई, को 36 प्रखंड विकास पदाधिकारियों का स्थानान्तरण आदेश ग्रामीण विकास विभाग ने निकाल दिया तो मैं जानना चाहता हूँ कि इनका आदेश कैसे चलेगा ? "जैक" का आदेश चलेगा या बिहार सरकार का आदेश चलेगा ? "जैक" को अधिकार दे दीजिये । दो आदेश कैसे चलेंगे ?

श्री तुलसी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विधानमंडल की बैठक की समाप्ति के बाद सभी दलों के नेताओं को बुलाकर इस पर राय लेकर निर्णय लिया जायेगा।

(इस अवसर पर भा०ज०पा० के कुछ माननीय सदस्यगण "वेल" में आ गए)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति । शांति । आप लोग पहले अपनी-अपनी जगह पर जा कर बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री तुलसी सिंह : महोदय, मेरी बात सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री तुलसी सिंह : महोदय, माननीय सदस्य मुझसे बात न करें । उनको जो कुछ कहना हो, आसन से अपनी बात कहें ।

उपाध्यक्ष : सब बात आ गई है । एक समय सीमा के अंदर इस समस्या का समाधान करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री तुलसी सिंह : महोदय, माननीय सदस्य बारी-बारी से बोलें ।

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कंट्राडिक्टरी है । सभी दल के नेताओं के साथ बैठक किया जाये ।

(इस अवसर पर कांग्रेस आई के माननीय सदस्यगण "वेल" में आ कर बैठ गये हैं)

श्री तुलसी सिंह : महोदय, मैं फिर कर रहा हूं कि जो चीज नियम के खिलाफ होगा, कानून के खिलाफ होगा, वह स्वतः रद्द होता है । सरकार वैसा कोई काम नहीं करेगी जो कानून और नियम के खिलाफ है । एक्ट ओर एग्रीमेंट के अनुसार जो है उसी का सरकार पालन करेगी ।

(व्यवधान)

महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार समाधान करेगी । लेकिन कानून के खिलाफ कोई काम नहीं होगा । कानून के खिलाफ कोई भी काम अवैध होगा । इसलिए सरकार कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी ।

(व्यवधान)

महोदय, मैंने हमेशा झारखंड के सभी लोगों की बात जानने का काम किया है । पहले भी किया है । मैंने अपने उत्तर के क्रम में कहा कि आवश्यकतानुसार इस पर भी कार्रवाई करेगी ।

महोदय, मैं फिर कह रहा हूं कि आवश्यकतानुसार इसके अनुरूप सरकार काम करेगी । जो पहले से करते रहे हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोग अपनी-अपनी सीट पर जाकर बोलिये। "वेल" से कोई बात नहीं नोट होगी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, उपेन्द्र नाथ दास, आप अपनी सीट पर जाइये ।

श्री रविन्द्र चरण यादव : महोदय, सदन में माननीय सदस्यों द्वारा समस्या को उठाया जाना बाजिव है लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कही जाय जो तथ्यहीन, बेबुनियाद और निराधार हो ।

(व्यवधान)

श्री तुलसी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि विधान-मंडल सत्र के समाप्त होने के तुरंत बाद सभी दलों के माननीय नेताओं से राय लेकर रास्ता तय किया जायेगा ।

श्री सुशील कुमार मोदी : वह बैठक कब होगी ?

(व्यवधान)

सरकार चाहती है कि विधान-मंडल का सत्र समाप्त हो जाय, फिर टल जायेगा। मंत्री जी, आप विधान-सभाध्यक्ष के चेम्बर में कल ही सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर निर्णय लीजिए ।

श्री तुलसी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विधान-सभाध्यक्ष के चेम्बर में बैठक करके निर्णय लेकर इसमें समय निर्धारित कर लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : सरकार ने उत्तर दिया है कि अध्यक्ष के चेम्बर में सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करके समस्या का समाधान निकाला जायेगा ।

श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव : समय-सीमा तय कर दिया जाय ?

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष भी सरकार से बात कर लेंगे । सरकार जब तैयार हो जायेगी, चलते सत्र के अन्दर ही बैठक बुलाकर तय कर लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर कांग्रेस के माननीय सदस्यगण सदन के "वेल" में आ गए)

श्री तुलसी सिंह : महोदय, अध्यक्ष जी के चेम्बर में सभी दलों के माननीय नेताओं के साथ बैठकर तय कर लिया जायेगा । ज्यों ही एसेम्बली समाप्त होगा, हमलोग बैठकर कर लेंगे ।

(व्यवधान)

आज सदन की बैठक समाप्त हो जाने के बाद हमलोग अध्यक्ष के चेम्बर में बैठकर तय कर लेंगे ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : चलते सत्र में वार्त्ता करके सभी दलों के नेताओं के साथ अध्यक्ष के चेम्बर में बैठकर तय कर लिया जाय ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह, आप अपना कटौती का प्रस्ताव मूभ करें ।

(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र नाथ दास : उपाध्यक्ष महोदय, सारी सूचना रद्द कर दी जाय......

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री तुलसी बाबू ने जो जबाब दिया है, उससे हमलोगों को थोड़ा संतोष हुआ । वे हर दल के माननीय नेताओं के साथ अध्यक्ष के चेम्बर में बैठना चाहते हैं । समस्या गंभीर है लेकिन एक बात कहने में उन्होंने कोताही की है । हमलोगों ने प्रोपोज़ल दिया था कि तब तक के लिए झारखंड एटोमस काउंसिल का आदेश (औपरेशन) बन्द रहेगा। मंत्रीजी इस तरह का आदेश नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

आदेश स्थगित करें, यह बात मंत्रीजी नहीं बोल रहे हैं ।

श्री तुलसी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यही तो तय करना है । जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उस तिथि को तय करने के लिए अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में बैठकर, उसमें सभी दलों के नेताओं एवं माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ बैठकर निर्णय लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की जो घोषणा है, उससे हमलोग असंतुष्ट हैं और ये गलत राज्यविरोधी काम कर रहे हैं । सभी दलों के कहने के बावजूद आदेश को स्थगित करने के लिए तैयार नहीं हैं । हमारा विरोध बरकरार रहेगा, इसी विरोध के साथ हमलोग सदन का बाकआउट करते हैं ।

(इस अवसर पर भारतीय कांग्रेस पार्टी (आई) के सभी मा० सदस्यगण सदन का बहिस्कार किये)

श्री उपेन्द्र नाथ दास : उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निर्देश दें, आप

सर्वोपरि हैं । सरकारी अधिसूचना रद्द करें, अराजकता की स्थिति को समाप्त करायें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह ......

(व्यवधान)

श्री वृशिण पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ ।

उपाध्यक्ष : आप बोलिए ।

श्री संकटेश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय,..........

उपाध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य वृशिण पटेल जी को बुला लिया है, इसके बाद आप बोलियेगा ।

(व्यवधान)

श्री वृशिण पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के सवाल पर खड़ा हूँ । कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सरकार के समर्थक दल हैं ओर विपक्ष में आपलोग. इनका सीट आवंटित करा दिए । यह परम्परा रही है कि सरकार के जो समर्थक दल होते हैं, वे सत्ता पक्ष की ओर बैठते हैं, इसलिए आप इनको व्यवस्था करायें ।

(व्यवधान)

झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग इस सरकार के समर्थक हैं । आखिर समर्थक क्यों है, यह तो समझने की बात है, इसमें कहने की क्या बात है ।

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री वृशिण पटेल जी ने जो आग्रह किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सदस्य हैं, वे सत्ता पक्ष के समर्थक दल हैं, उनको इधर आ जाना चाहिए । लेकिन महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा हमारे दल के सदस्य हैं, उनको वहाँ नहीं बैठना चाहिए था, उनका यहाँ पर सीट है, इसपर आप

अपना नियमन दीजिए ।

उपाध्यक्ष : श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह ।

श्री सुशील कुमार मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आज या कल स्पीकर साहेब के चेम्बर में बैठ करके इसका निदान किया जाय । सत्र के बाद बैठक हो, इसके लिए हम तैयार नहीं हैं । आज या कल या परसों स्पीकर साहेब के चेम्बर में बैठ करके इसका निदान हो ।

श्री तुलसी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज ही सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद स्पीकर साहेब के चेम्बर में बैठ करके तिथि के बारे में निर्णय ले लेंगे ।

उपाध्यक्ष : श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह ।

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव पर 2-3 मिनट बोलूंगा और हमारे बदले माननीय सदस्य श्री छत्रुराम महतो जी बोलेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में माननीय मंत्री जी बोलेंगे लेकिन जो स्थिति है, पूरे प्रदेश में बिजली नहीं मिल रही है, ट्रांसफर्मर बदलने के लिए पैसा देना पड़ता है, ट्रांसफर्मर में तेल डालने के लिए पैसा देना पड़ता है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि वे इसकी विधिवत जांच करायें ।

महोदय, विधायक आवास में भी प्रोबलम है, पता नहीं माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि नहीं । आर-ब्लॉक, एम0एल0ए0 फ्लैट में बिजली की कमी है, पहले कार्यपालक अभियंता देखने के लिए आते थे लेकिन अब तो स्थिति यह है कि उनके यहां आदमी जाता है, तब भी नहीं आते हैं । विधान-सभा चलता है, उस समय भी वे देखने नहीं आते हैं । उनको सुचना देने पर भी कनीय अभियंता या केयर-टेकर भी नहीं आता है तो और लोगों की बात तो छोड़ दीजिए । माननीय सदस्यों की समस्या है, उनके घर में पंखा नहीं है । इसके लिए जब कहा जाता है तो जबाब मिलता है कि इसके लिए सिफारिश करना होगा तब पंखा लगेगा । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी जांच कराईये और इतनी व्यवस्था तो कीजिए कि विधायक को इतनी रोशनी दी

जाय, जिससे वे विधायी कार्य तो कर सके, इतना पंखा तो दीजिए, जिससे वे गर्मी से बच सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, इसी सदन में जब श्री बिन्देश्वरी दूबे एप्रोप्रियेशन बिल पर बोल रहे थे और डा0 जगन्नाथा मिश्रा जी ने इन्टरप्सन करते पूछा कि झंझारपुर का क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमने तो बता ही दिया, हम बोल ही रहे थे । महोदय, उसी पर उनको एक कहानी याद आयी और बताया कि एक राजा से पुरोहितों ने कहा कि खाना के लिए हमलोग मर रहे हैं तो राजा ने मंत्री को बुलाया और उनसे कहा कि पुरोहितों को एक क्विंटल चावल और एक क्विंटल दूध दे दो और मंत्री ने पुरोहित को दे दिया और फिर दूसरे दिन राजा ने मंत्री से पूछा तो मंत्री ने राजा को बता दिया कि लोग दुध-भात खा रहे हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि आप दूध-भात खाईये लेकिन विधायकों पर भी ध्यान दीजिए । पदाधिकारी लोग निरंकुश हो गये हैं । आप उनको सिर्फ कानूनी परिक्रमा मत कराईये । मंत्री जी, बैठ करके इस पर भी ध्यान दीजिए । विधायकों के यहां जब यह हाल है तो प्रदेश के लोगों का क्या हाल होगा, यह आप समझ सकते हैं, इसलिए मंत्री जी इस पर आप ध्यान दीजिए ।

श्री छत्रुराम महतो : उपाध्यक्ष महोदय, उर्जा विभाग पर जो कटौती प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य के विकास वहां की उर्जा शक्ति, बिजली का उत्पादन, बिजली का वितरण और बिजली की व्यवस्था पर वह निर्भर करता है । हम बिहार के बिजली की स्थिति पर अगर गौर करेंगे तो बहुत निराशाजनक स्थिति आती है । बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है, जहां पर आप दूसरे-दूसरे मामले में विकास की बात का दावा कर सकते हैं लेकिन बिजली के संरक्षण के मामले में इतना नीचे हैं कि हम बिहार के विकास की कल्पना इस सरकार से नहीं कर सकते हैं ।

आपको वह डाटा से स्पष्ट हो जाएगा । जहां, दूसरे प्रान्तों में जो मुझसे

छोटे-छोटे प्रान्त हैं, उन प्रान्तों में हाइड्रो-इलेक्ट्रीसीटी या थर्मल पावर से जो बिजली उत्पादन होता है उसी तुलना में हम कितना ज्यादा या कम हैं, आप देखियेगा, हरियाना जो हमसे छोटा प्रान्त है वहां हाइड्रो-इलेक्ट्रीसीटी 883 मेगावाट बिजली पैदा होता है और थर्मल पावर के माध्यम से 896 मेगावाट बिजली पैदा होता है । उसी तरह से, पंजाब में 1798 मेगावाट बिजली पैदा होता है, राजस्थान में 967 मेगावाट बिजली पैदा होता है और थर्मल पावर से 1013 मेगावाट बिजली पैदा होता है । उसी तरह से, गुजरात में 487 मेगावाट बिजली पैदा होती है और थर्मल पावर से 4841 मेगावाट बिजली पैदा होती है । सबसे नीचे, इतना डिटेल में नहीं जा कर हम यही बतलाना चाहेंगे कि हमारे बिहार राज्य में बिजली का उत्पादन हो रहा है चाहे वह हाइड्रो-इलेक्ट्रीसीटी के माध्यम से ही, चाहे थर्मल पावर के माध्यम से हो, सबसे कम है । वह केवल हमारे यहां जो बिहार में हाइड्रो-इलेक्ट्रोसीटी से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वह 164 मेगावाट है और थर्मल पावर से जो उत्पादन हो रहा हैं वह 1603 मेगावाट है- टोटल 1767 मेगावाट बिजली बिहार में पैदा होता है । बिजली के लिए हमारे बिहार प्रान्त में जो पैसा लगाया जाता है, उससे स्पष्ट होगा कि 50 वर्षो के अन्दर, चाहे सरकार किसी की भी हो, यह आठ वर्ष जो राष्ट्रीय जनता दल यानी लालूजी की सरकार रही, उसमें भी बिजली का उत्पादन के लिए जितनी गंभीरता बरतनी चाहिए थी, जितना सिरियस होना चाहिए था, वह नहीं हुआ । इसका कारण है कि बिजली मद में जो खर्च किया गया है वह वर्ष 1994-95 में चार अरब अठासी करोड़ छियासठ लाख रूपये खर्च हुए हैं, वर्ष 1995-96 में 3 अरब, 78 करोड़, 89 लाख रूपये खर्च हुए हैं उसी तरह से 1997-98 में 3 अरब 87 करोड़ 88 लाख रूपये खर्च हुआ है । इस साल 1998-99 में आपने जो मांग प्रस्तुत किया है उसमें है 4 अरब 38 करोड़ 27 लाख छियासी हजार रूपया आप इस मद में खर्च करने जा रहे हैं । इससे स्पष्ट होता है कि शुरू से लेकर और 1995-96 से लेकर 1998 तक या 1999 तक जो बिजली के उत्पादन के मद में खर्च किया जा रहा है वह इतना कम है कि हम बिजली के उत्पादन की आशा ही नहीं कर सकते हैं और जहां बिजली का संरक्षण और अपव्यय इतना ज्यादा हो, वहां बिहार में कहीं से भी विकास की कल्पना नहीं

कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बिजली हर चीज के उत्पादन के लिए एक जीवन प्रदान करने वाली शक्ति है तथा जहां हम उद्योग-धंधों की बात करते हैं, वहां देखते हैं कि हजारो-हजार उद्योग बिजली के आभाव में बंद पड़े हैं । किसानों के सिंचाई का जो माध्यम है वह तो करीब-करीब ठप्प है । छोटानागपुर में भालको के माध्यम से सिंचाई की जाती है जो लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई की जाती है । जहां भालको बना है या लिफ्ट इरीगेशन को बिजली की आपूर्त्ति नहीं हो पा रही है । और, इसी तरह से बिजली के उत्पादन का जो हमारा श्रोत है वह दो प्रकार से बिजली का उत्पादन करते हैं: एक तो, ताप बिद्युत से बिजली का उत्पादन करते हैं और दूसरा, बिजली बिद्युत केन्द्र से बिजली का उत्पादन करते हैं । ताप बिद्युत से बिजली का उत्पादन होता है उसकी क्षमता 1380 या 1400 मेगावाट के आस-पास मानता हूं लेकिन वस्तुतः हमें जो बिजली अभी मिल रही है वह 600-700 से ज्यादा मेगावाट नहीं है । पतरातु में जो ताप बिद्युत केन्द्र है उसकी स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि आज से चालीस-पैंतालीस वर्ष पहले जो पतरातु थर्मल पावर बना, उसका 10 यूनिट है, जिसमें से केवल पांच यूनिट चालू है जिसमें केवल 3 ही पर बिजली का उत्पादन हो रहा है । उसी तरह से बरौनी की भी यही स्थिति है। आधे इकाई से अधिक खराब पड़ी हुई है । उसी तरह से मुजफ्फरपुर में आधे से अधिक इकाई बेकार पड़ी हुई है ।

आज जो बड़े बिजली बिद्युत गृह हैं और उनके माध्यम से जो उत्पादन होता है उस से 149 मेगावाट बिजली पैदा होती है, मात्र 149 मेगावाट । डेहरी में 6.6 मेगावाट, बारून में 3.3 मेगावाट, बालमिकिनगर में 15 मेगावाट बिजली पैदा होती है । इसके अलावा जो छोटे छोटे बिजली उत्पादन केन्द्र हैं उनसे भी बिजली पैदा होता है । हम सरकार से जानना चाहते हैं कि वह बिद्युत के मामले में इतनी लापरवाह क्यों है । आप गांव के विकास की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, मगर मैं कहता हूं कि बिहार विकास के मामले में बहुत पीछे है, औद्योगिक विकास के मामले में बहुत पीछे है

क्योंकि बिजली की आपुर्ति ठीक ढंग से नहीं होती है । अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में जहां यह सरकार दावा करती है कि 2000 ई0 में सभी गांवों को विद्युतिकृत कर देंगे मगर गांव के विद्युंतिकरण की स्थिति यह है कि यहां 66,546 गांव हैं जिसमें 46,663 ऐसे गांव हैं जहां विद्युतिकरण किया गया है और वह भी जो हुआ है वह कागज पर अधिकतर है । हजारों हजार गांव ऐसे हैं जहां पोल गड़वाने के बाद भी, तार लगने के बाद भी विद्युत की सप्लाई नहीं हो रही है । जिस गांव में पोल लग गया उसको विद्युतिकृत मान लिया गया है, जिस गांव में तार चला गया है उसको विद्युतिकृत माना लिया गया है, जिस गांव में ट्रांसफार्मर लग गया है उसको विद्युतिकृत मान लिया गया है, यानी उन सारे गांव को विद्युतिकृत मान लिया गया है जहां, तार, पोल, ट्रांसफार्मर चला गया है मगर वास्तविकता यह है कि वहां बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है । लोग अभी भी अंधेरे में रह रहे हैं । गांवों के बारे में इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें खुद इन्होंने स्वीकार किया है कि जो संतुलन होना चाहिए था बिहार राज्य में वह नहीं हैं । बिहार राज्य की आबादी पूरे देश की आबादी का 10 प्रतिशत है । यहां की जितनी बड़ी आबादी है उसके अनुपात में बिजली पर जो प्रयोग कर रहे हैं वह बहुत कम है इसलिए हम जानना चाहते हैं कि यह सरकार क्या करना चाहती है बिजली के उत्पादन के मामले में । जो सरकार की योजना है, जिन योजनाओं को आपने केन्द्र सरकार के पास भेजा है और केन्द्रीय आयोग को भेजा है, इन योजनाओं को सम्पादित कराने में और कितना समय लगेगा । बिहार सरकार बिजली उत्पादन के क्षेत्र में खर्च करने के लिये जो पैसा देती है वह सही रूप से खर्च नहीं होता है । आज जो गांव की स्थिति है वह तो बहुत बुरी है ही, इसकी स्थिति को छोड़ दें, शहरों की जो स्थिति हो गयी है वह भी अच्छी नहीं है । शहरों में जो बिजली की सप्लाई हो रही है वह भी ऐसी है कि महीने में 12 दिन या 14 दिन ही बिजली सप्लाई होती है और वह भी 2-3 घंटे । विशेष करके बिजली ऐसे समय में गायब रहती है शाम से लेकर रात 2 बजे या 10 बजे तक । जब बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता रहती है उस वक्त बिजली गायब रहती है, जब घरेलू काम के लिए बिजली की आवश्यकता रहती है तो बिजली गायब रही है और जब घर के लोग सोने के लिये जाते हैं तो

बिजली हाई भोल्टेज के साथ आ जाती है लेकिन भोजन बनाने के समय, भोजन लेने के समय या पढ़ाई के समय बिजली की सप्लाई आप नहीं कर पाते हैं। सोने के बाद बिजली आती है, साने के पहले बिजली मिलती नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि तेनुघाट विद्युत निगम जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, तेनुघाट विद्युत निगम की स्थापना के इसको बनने में कई साल लगे। 96-97 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, लालूजी गये थे और वहां जो विद्युत केन्द्र बना है तेनुघाट में, टी0टी0पी0एस0 में जो सरकार की योजना थी कि तीन चरणों में 1550 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। आप जानते हैं कि छोटानागपुर में विद्युत उत्पादन केन्द्र हैं। वहां उद्योगों का जाल बिछा हुआ है। जितनी बिजली वहां चाहिए उतनी आपूर्ति नहीं हो पाती है। वहां अगर कोई सहयोगी हो सकता है तो टी0टी0पी0एस0 का प्रोजेक्ट हो सकता है। इसलिए जब चीफ मिनिस्टर उसका उद्घाटन करने के लिए गये थे तो उन्होंने कहा था कि एक साल के अन्दर इसके दूसरे चरण का काम प्रारंभ हो जायेगा और दूसरे चरण का जो काम प्रारंभ होने वाला है उसमें तीन इकाईयां बनने वाली है। उसमें 210, 210, 210 की तीन इकाई बनने वाली है और फिर जो चार इकाई बनने वाली है वह 500 मेगावाट की बनने वाली है। इस तरह से टोटल 1550 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की योजना सरकार की है लेकिन केवल 420 मेगावाट पैदा करके छोड़ दिये। इनके इंजीनीयर और जो विद्युत बोर्ड के लोग हैं या जो ठीकेदार हैं, जिन कम्पनियों को काम दिये हैं, वह कम्पनी किस तरह से काम कर रही हैं जैसे भेल को काम दिये, इन्होंने बड़े बड़े कम्पनियों को काम दिया। इनका आइ0ए0एस0 एक प्लान्ट है जिममें छाई जमा होता है और वह प्लान्ट जैसे ही इनका दूसरे चरण का विद्युत उत्पादन का काम शुरू हुआ, छः महीने के अन्दर इनका आइ0ए0एस0 प्लान्ट धंस गया और जो दो इकाई थी उन इकाईयों में बिजली पैदा करना था। वह 420 मेगावाट बिजली पैदा नहीं करके केवल 150 या 160 मेगावाट बिजली पैदा होती है। और वह भी 160 से इनका पूर्णोधार या जीर्णोधार का काम चल रहा है लेकिन यह इतना मंथन गति से काम चल रहा है कि जैसे लगता है कि सरकार का इस पर ध्यान

टी0टी0पी0एस0 पर है ही नहीं । यह जानकारी आपको टी0टी0पी0एस0 से जहां कोयला जा रहा है, प्लान्ट को जा रहा है, कोलियरी से कोयला जा रहा है वह ट्रक से कोयला जाता है । एक तो ट्रक से जो कोयला जाता है उसकी क्वालिटी क्या है । बराबर हम देखते हैं, रोड में, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जब ट्रक पर कोयला लोड कर दियाँ जाता है तो 20 प्रतिशत से ज्यादा कोयला नहीं लगता है । बाकी सभी पत्थर और बड़े-बड़े चट्टान रहते हैं । उस ट्रक में जिसमें हमने जाकर देखा कि पत्थर का चट्टान है और उस पत्थर में चट्टानों को छिपाकर यह दिखाया गया कि यह कोयला जा रहा है । इस तरह कोयले की क्वालिटी तो इनका निम्न स्तर का है जिससे प्लान्ट सही रूप से चल रहा ही नहीं सकता है और कोयला का स्टॉक जो कोलियरी में दिखाया जा रहा है उससे लगता है कि जानबूझ करके प्लान्ट को बर्बाद करने की, प्लान्ट को समाप्त करने की योजना चल रही है । दूसरी बात है कि जो रोड है, हमने बार बार उर्जा मंत्री को कहा कि जो रोड है इनका सिवान से लेकर टी0टी0पी0एस0 तक, यह मात्र 8-9 किलोमीटर रोड है । 8-9 किलोमीटर की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब उसमें डम्फर भी चलना बन्द हो गया है । 4-5 फीट गड्ढा हो गया है और उसकी मरम्मति नहीं हुई है । फरवरी महीने में उसका टेंडर हुआ था। एक करोड़ रूपया के आसपास है । उस टेंडर को भी टेकनिकल गड़बड़ी बता कर रोक दिया गया । वर्षात का समय आ गया है । गडढ़ा भी भर नहीं सकते हैं, डम्फर जाना बन्द हो गया है । रेलवे लाइन 10 साल से बन रहा है । रेलवे लाइन बनने से जो आपको कठिनाई उत्पन्न हुई है, जिन लोगों ने अपनी जमीन दी है, जिनकी अपनी जमीन है, जिनका कागजात है, जिनका सारा सर्वे खतिहान का जमीन है, रयैती जमीन है, आप उन लोगों को मुआबजा नहीं दिये हैं, बावजूद आप पुलिस के बल पर, फोर्स के बल पर काम करवा लेते रहे हैं और गांव के लोग जब इनको रोक देते हैं तो आप गोली का प्रयोग करते हैं, उन्हें जेल में बन्द करने का काम करते हैं । हम चाहिते हैं कि नौकरी के लिए जो विधिवत हैं आप उनको नौकरी दीजिये । आप करते हैं कि गांव के लोग काम नहीं करने देते हैं । गांव के लोग कैसे काम करने देंगे । आप उनको विस्थापित किये, आप उनकी जमीन लिये लेकिन आप मुआबजा का पैसा नहीं दिये । जो

काम चल रहा है उसमें आप जबरदस्ती कर रहे हैं, उसमें आप पैसा नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि वह जो टी0टी0पी0एस0, ललमटिया का जो प्रोजक्ट है इसके लिये आपने दूसरे चरण का काम शुरू करने के लिए कहा है। आपने कहा है कि 100 करोड़ रूपया हमने दिया है। 100 करोड़ रूपया से क्या होगा। जहां अभी 500 करोड़ रूपये की आवश्यकता है वहां आपने 100 करोड़ का प्रवधान किया है। और इसमें आपने कहा कि 100 करोड़ में से 50 करोड़ रूपया जो पुराने बिल हैं उनके भुगतान में जायेगा और जो 50 करोड़ रूपया है उससे वे प्लानिंग बनायेंगे और उसके बाद वे काम शुरू करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह काम कब से दूसरे चरण का आरम्भ करना चाहते हैं और इसके लिए कितना पैसा देना चाहते हैं।

इसी तरह से कहलगांव में जो एन0टी0पी0सी0 का पावर स्टेशन है वह भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, बहुत से यूनिट कितने दिनों से बेकार पड़े हुए हैं और वहां पर काम ठीक से नहीं कर रहा। मैं इन सब चीजों की ओर इनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आप जान-बूझ कर थर्मल पावर को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। आपने मुजफ्फरपुर थर्मल पावर को बजट में प्रावधान किया है, इसके लिए कोयला आयोग छोटानागपुर से, सारी चीज़ें आयेंगी छोटानागपुर से और उसकी ढुलाई पर कितना पैसा खर्च होगा। मुजफ्फरपुर को पैसा दिया है, जो नये प्रोजक्ट को पैसा दिये हैं लेकिन जो पुराने प्रोजेक्ट छोटानागपूर में, उनके काम को आप कराने के लिए भी पैसा दीजिए, जहां पर काम करने की आवश्यकता है, उसमें पैसा नहीं देकर इसे खटाई में डालना चाहते हैं। इसी तरह से इनकी जो सबसे बड़ी कठिनाई जो बिजली विभाग में है वह है बिजली की चोरी, इस चोरी को रोकने में यह सफल नहीं हो रहे हैं और इसमें सफल नहीं होने के कारण इनको प्रति वर्ष जो घाटा हो रहा है, जिसके कारण बिजली के विकास का काम यह नहीं कर सकते हैं और इनके अधिकारी और कर्मचारी चाहे रिडिंग डिपार्टमेंट में हो, या विलिंग में हों; काफी चोरी कर रहे हैं और इसके चलते उपभोक्ता परेशान है। उपभोक्ता को ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। उपभोक्ता पैसा देने के लिए तैयार है

और कहता है कि जो मुनासिब पैसा उसे लेकर बिजली का लाईन दीजिए लेकिन कोई मुनासिब पैसा लेने के लिए इनके विभाग में तैयार नहीं है, जब वहां कोई जाता है तो उसके साथ सैटलमेंट कर लीजिए यानी पांच हजार रूपया दे दीजिए और थोड़ा सा पैसा बोर्ड में जमा कर दीजिए, इस तरह से बिजली विभाग में काम हो रहा है । घोर अनियमित्ता है बिजली विभाग में और इस घोर अनियमित्ता को समाप्त करने के लिए अगर मंत्री महोदय कार्रवाई नहीं करेंगे, काररार कदम नहीं उठायेंगे तो बिजली के मामले में कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं । आप बिजली विभाग के मामले में कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं । आज बिजली विभाग सबसे बदनाम विभाग है । अगर हमलोगों से कोई वोटर बात करता है और कहता है कि हमारे यहां लाईन नहीं गया है तो हमलोग कहते है कि अच्छा है लाईन नहीं गया, नहीं तो ल न जाने के बाद जैसे कहावत है कि मनेर का लड्डु जो खाये वह भी पछताये और जो न खाये यह भी पछताये । यही हालत बिजली विभाग का है, अगर बिजली लग गयी तो अपको बिजली नहीं मिलेगा, यदि बिजली नहीं लगेगी तो ढ़िवरी से भी काम चला लेंगे, लालटेन से नहीं चला सकते हैं, ढ़िवरी से चला सकते हैं । क्योंकि ढ़िवरी और दीया का ही उपयोग बिहार में होता है । इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं ।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सभी जगह ढिवरी नहीं जलता है, जहां पर बिजली नहीं है वहां पर लालटेन जलाईये, ढिवरी नहीं जलाईये, लालटेन ही सब जगह है । लालूजी के लालटेन से नई रोशनी मिलेगी बिहार के गरीबों को ।

श्री उपेन्द्र नाथ दास : उपाध्यक्ष महोदय, सभी लालटेन बुझ गया है, इनके नेता का यह नारा फेल कर गया है कि जिसके पास है लालटेन, वही जायेगा पार्लियामेन्ट । इसका उदाहरण यहां पर बैठे हुए लोंग धराशायी हो चुके हैं । किरासन तेल बाजार में कालाबाजारी में मिल रहा है, इसलिए लालटेन अब नहीं जलने वाला है ।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : लालटेन की रोशनी को आप देख लीजिए, इस तरफ क्या हालत है । ढिवरी जलायेंगे तो धुआं लगेगा और अंधे हो जायेंगे।

श्री छत्रु राम महतो : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सौर ऊर्जा के बारे में कहना चाहता हूं । सौर ऊर्जा का सरकार का कार्यक्रम है, चकाई और गया में इसके लिए स्टेशन स्थापित करने की बात है लेकिन आज तक यह नहीं स्थापित हो सका है, यह सरकार के विचाराधीन है । और इसमें अभी तक फाईनल विचार नहीं किया गया है कि कब से सौर ऊर्जा को शुरू किया जायेगा, इसलिए उसे शीघ्र आरम्भ किया जाए । हजारों हजार ट्रान्सफार्मर जले हुए हैं । इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि आपने ट्रान्सफार्मर बदलने के लिए जो मापदंड तय कर रखा है कि ७५ प्रतिशत् भुगतान होने पर ही दिया जायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि ७५ प्रतिशत् भुगतान करने में गांव के लोग सक्षम नहीं हैं तो आप इतनी रियायत तो दे सकते हैं, अगर वे ४० प्रतिशत्, ५० प्रतिशत् भी वे भुगतान कर देते हैं, बिजली लाईन आप उनको दे देते हैं तो बाकी जो भुगतान की राशि है उसे बाद में दिया जा सकता है । इसलिए हजारों-हजार ऐसे गांव है जहां के तार की चोरी हुई है, पोल की चोरी हुई है जहां बिजली नहीं जल रही है- राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत विधान-सभा में सरकार ने घोषणा की थी ग्रामीण विद्युतीकरण में जो कई सौ करोड़ केन्द्र सरकार का इनके पास है, यह जो राशि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये दी गई है उसका उपयोग नहीं हो रहा है । इसलिये जहां-जहां विद्युतीकरण में बाधा हो गई है, पुराने गांव में विद्युतीकरण की योजना है और नये गांव में विद्युतीकरण की योजना है- ये योजनायें आपकी कहीं नहीं चल रही है । ग्रमीण विद्युतीकरण में जिन गांवों को जोड़े थे, इनमें से बहुत गांवों में पोल गाड़ दिये गये थे, उनमें कम से कम तार देकर विद्युतीकरण करने का काम कीजिये, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं । सरकार को जो नीति है, यह नीति बहुत गलत है, इसलिये हम चाहते हैं कि विद्युतीकरण में जो खर्च होता है, सही खर्च हो............

(व्यवधान)

श्री देव दयाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वांयट ऑफ इनफारमेंशन पर खड़ा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस गांव में, जिस मुहल्ला में ट्रांसफर जल गया है, वैसे सरकार का शर्त्त है ७५ प्रतिशत् भुगतान करने का, पैसा देने का, इतना भुगतान करने पर ही लगेगा, हुजूर अब इसमें मुझे कहना है कि बड़े लोग के पास जो पैसा जमा रहता है, उनका लाईन काट दीजिये, बाकी जो छोटे-छोटे जो लोग हैं, जिनके पास बकाया नहीं हैं, उनके चलते ट्रांसफार्मर नहीं दीजियेगा तो उन्हें बिजली कैसा मिलेगा- यही मैं सूचना देना चाहता था ।

श्री विजय सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ५२ घंटा अनशन पर बैठ कर आपके बीच में आया हूँ । मैं ११ तारीख को १० बजे दिन से अनशन पर बैठा था दानापुर के गणेश बुक हाऊस के पास । बिहार सरकार का कोई अधिकारी नहीं, राज्य-मंत्री नहीं, उनके विद्युत बोर्ड के कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आये । दानापुर में बिजली संकट एक महीने से है, वहाँ पर बिजली का घोर संकट है, चारो तरफ एक महीना से अंधेरा था, इसके लिये दानापुर में रोड पर अनशन करने का कार्यक्रम चला, लेकिन बिहार सरकार कान में तेल डालकर सोयी हुई है । अखिर में हारकर मैं ११ तारीख को १० बजे दिन से अनशन पर बैठ गया, बैठने के बाद भी न उर्जा विभाग का कोई अधिकारी, मंत्री- कोई सुनने नहीं आया, नहीं देखने आये कि हमारा विधायक मर रहा है या जी रहा है, इसके बाद हार कर अनशन पर बैठे । कल रात १२ बजे, दानापुर के अनुमण्डलाधिकारी ने थ्रेटनिंग दिया कि अनशन तोड़ते है या नहीं ? तीन बार आये और कहें कि अनशन तोड़ते है या नहीं, तो मैंने जबाब दिया मैं अनशन तोड़ने वाला नहीं हूँ । लाचार होकर मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, को पत्र दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय का जब पत्र आया तब जिलाधिकारी को बुलाकर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जाइये विधायक जी का अनशन तोड़वाइये । इस बीच कोई देखने नहीं आये यह दुर्भाग्य है, अंत में ५२ घंटा का अन्शन तोड़ना पड़ा । नई विद्युतीकरण का बात तो छोड़ दीजिये, आप पुराने विद्युतीकरण नहीं कर पा रहे हैं । एक महीना से दानापुर में हालत ऐसी है कि मत पूछिये, दानापुर में पानी की भी हालत वैसे ही हैं, मैं पी0एच0ई0डी0 मंत्री श्री मुंशी लाल राय के आवास पर एक बार नहीं सैकड़ों बार गया और कहा कि इस भीषण गर्मी

में, इस तपती धूप में लोग पानी के लिए त्राहि-त्रहि कर रहे हैं, सैंकड़ों बार उनके पास गये, लेकिन एक चापाकल वे नहीं दिये जब कि पहले के मुख्यमंत्री (श्री लालू प्रसाद) दानापुर, मनेर से लेकर बख्तियारपुर तक मंत्री को लेकर घूमें थे और घोषणा की थी कि जितना चापाकल चाहिये हम देंगे। लेकिन एक भी चापाकल देने का काम सरकार ने नहीं किया है। बिहार सरकार ने एक भी चापाकल नहीं गाड़ा है। मैं चैलेंज करता हूं।

महोदय, सरकार नये विद्युतीकरण की बात करती है लेकिन जो पुराना विद्युतीकरण है उसमें भी बिजली आपूर्त्ति करने का काम नहीं करती है, ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है। यदि एक सप्ताह के अंदर इसमें सुधार नहीं हुआ तो मैं विशाल जूलुस लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन करूंगा।

श्री जयप्रकाश ना० यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य, श्री विजय सिंह यादव ने बताने का काम किया कि वे बिजली के लिये, पानी के लिये अनशन पर बैठे थे।

महोदय, सदन चल रहा है। माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने के लिये यह सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। आज ही बिजली के डिमांड पर बहस हो रही है जहां उच्च पदाधिकारी से लेकर हमारे माननीय उर्जा मंत्री भी हैं। यहां पर माननीय सदस्य आपनी बात नहीं कहकर दानापुर में अनशन पर बैठकर पोलिटिकल माइलेज लेने का काम कर रहे हैं कि हम भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बिजली सरकार देगी। जहां सदन में बिजली के डिमांड पर बिहस हो रही है तो माननीय सदस्य सदन में अपनी बात कहते। माननीय लोक स्वा0 अभियंत्रण विभाग के मंत्री श्री मुंशीलाल राय जी भी सदन में बैठे हुये हैं। उन्होंने स्वयं अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया है माननीय सदस्य के कहने पर नहीं।

श्री देव दयाल : माननीय सदस्य ने अपनी बात कहकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है और जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि सरकार कर रही है।

श्री जयप्रकाश ना० यादव : मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को कहने का भी हक है जैसे आपको वहां हक हासिल है ।

श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूं । महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आम जनता की आंकाक्षाओं की पूर्त्ति के लिये उसकी आवश्यक मांगों की पूर्त्ति के लिये बिजली और पानी जैसे गंभीर संकट को देखते हुये, जनता की दुर्व्यवस्था को देखते हुये अगर माननीय सदस्य, श्री विजय सिंह यादव ने भावना में आकर इस सदन में अपनी व्यथा को बताया है । वे अनशन पर बैठे रहे, कोई उनकी सुधि लेने नहीं गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, के पहल पर वे यहां आये हैं तो माननीय मंत्री को इस रूप में बयान नहीं देना चाहिये जिस रूप में उन्होंने दिया है । यह खेद का विषय है । माननीय सदस्य ने अपनी व्यथा को सुनाया है एक रेसपोंसिवल मंत्री को इस तरह से जन प्रतिनिधि की भावना के प्रतिकूल बात नहीं करनी चाहिये । यह सदन की गरिमा का सवाल है ।

श्री जयप्रकाश ना० यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने उत्तरदायित्व और सरकार का जो काम है उस काम को किया है । सरकार स्वयं अपने कामों को देख रही है । माननीय सदस्य आपनी बात कहें । मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं और सही हूं ।

श्री उपेन्द्र नाथ दास : आपने सदन को प्लैटफार्म क्यों कहा ? यह प्लैटफार्म नहीं है आपको जानना चहिये ।

श्री जयप्रकाश ना० यादव : प्लैटफार्म असंसदीय शब्द नहीं है जाकर पढ़िये।

श्री उपेन्द्र नाथ दास : दानापुर में माननीय सदस्य ने कहा कि बिज़ली नहीं है पानी नहीं है और लाचार होकर विवश होकर अनशन पर बैठे लेकिन इनमें इतनी गैरत नहीं है कि सरकार के मंत्री और पदाधिकारी जाकर देखें कि हमारे विधायक अनशन पर क्यों बैठे हैं ? वह देखने तो नहीं गए और यहां इस तरह की बात कर रहे हैं । इसी से सरकार की नीयत और मंशा का पता चलता है।

श्री जगदानंद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जयप्रकाश जी ने इतना ही कहा कि आप जिस विषय को उठाना चाहते थे आज इस सदन में उसी के ऊपर सबसे बड़ी बहस है और जो बात वहां कह रहे थे उससे यह बड़ी जगह है । जनता की बात उठाने का यह सदन सबसे बड़ा प्लेटफार्म है अब इसे अन्यथा मत लीजिये । जनता की बात कहने की जो समस्या आप वहां सड़क पर बैठकर कह रहे थे । आप हमारे माननीय सदस्य है । आप आम जन की लड़ाई लड़ सकते थे ।

श्री उपेन्द्र नाथ दास : यही बात जाकर समझा कर उनको ले आते, आप अपनी सहृद्‌यता दिखाते ।

श्री जगदानंद सिंह : मैं फिर कह रहा हूं । 10 मेगावाट के ट्रांसफरर्मर थे यानी 5-5 मेगावाट के दो ट्रांसफार्मर थे । महोदय, वह जल गए किसी गलती से जल गए मैं यह बात नहीं कहना चाहता हूँ । सरकार ने तात्परता बरत कर बिहार में जहां भी हो तीन तीन मेगावाट का ट्रांसफार्मर यानी दो ट्रांसफार्मर 6 मेगावाट का तत्काल लगाकर काम चलाया, यह कोई साधारण काम नहीं था और वहां का जो हमारा लोड था उस लोड में से पी0एच0ई0डी0 से लेकर और उससे लेकर कैनाल के बगल में जो सबस्टेशन है उसमें लोड ट्रांसफर कर दिया उस रूरल इलाके का और हमारा दानों ट्रांसफार्मर थे तो 24 घंटा रोज पावर देते थे । इधर पावर की कमी है क्योंकि अभी तीन तीन के दो ट्रांसफार्मर हैं हम पॉच पॉच मेगावाट के दो ट्रांसफार्मर प्रोक्योर कर रहे हैं जो तत्काल कर लेंगे। अभी थोड़ी सी बिजली कटौती हो रही है । उसे मैं फ़िर कह रहा हूँ कि बिजली की अड़चन आती है । किसी ने कल्पना नहीं की थी पॉच पॉच मेगावाट का दानों ट्रांसफार्मर लगा और खराब हो गया जब बारिश हो रही थी, एक तरह से प्राकृतिक विपदा आयी । यह हम पर और आप पर दोनों पर परेशानी थी । हम उसको निरीह नहीं छोड़े बल्कि जो मौजूद साधन था उसको लेकर पहूंच गए। यह स्थायी व्यवस्था नहीं है, अस्थायी व्यवस्था है । माननीय सदस्य जानते हैं सरकार ने कितनी तत्परता दिखाकर कैन्टोनमेंट एरिया दानापुर के इलाके में 6 मेंगावाट का ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली देने का काम किया । थोड़ी से लोड

शेडिंग हो रही है । कहीं दिन भर में 18 घंटे, कभी 14 घंटे बिजली देकर हम राहत दिए हुए हैं लेकिन पाँच-पाँच मेगावाट के दो ट्रांसफार्मर प्रौक्योर कर रहे हैं उसे हम लगायेंगें । माननीय जयप्रकाश जी ने यह कहा कि यह सवाल यहाँ उठाते तो हम भी आपको यह सब बताते, सदन के माध्यम से राज्य की जनता जानती और माननीय सदस्य सुपरिचित होते । मैं फिर कह रहा हूं कि हर विषय को पौलिटिक्स का विषय नहीं बनाना चाहिए । हम और आप दोनों ऐसे नहीं हैं कि मिल जुलकर समस्या का हल नहीं कर सकते ।

श्री उपेन्द्र नाथ दास : दो दिनों तक जनता पानी और बिजली के अभाव में मर जाय ?

श्री जगदानंद सिंह : ऐसा नहीं है । आपको गलत सूचना है । आपको मैं कह रहा हूँ कि पी0एच0ई0डी0 का लोड 80 एम्पीयर था उसमें से 40 एम्पीयर के लोड का ट्रांसफर कर दिया है वहाँ जो कैनाल के बगल में सब स्टेशन है उसमें 40 एम्पीयर का लोड उस पुराने सब स्टेशन पर है । एक एक चीज से सरकार बाकिफ है । कब कौन परेशानो उठेगी यह कोई नहीं जानता लेकिन दुनिया में बिजली ऐसी नहीं है जो आसमान से टपकती हो, उसके लिए माननीय सदस्य इंतजाम करना पड़ता है । कितनी कितनी विपत्ति आती है और उसमें सरकार और जनता को मिलाकर निपटना होता है । मैंने कहा तीन तीन के दो ट्रांसफार्मर लगे हैं और हम पाँच पाँच मेगावाट के दो ट्रांसफार्मर प्रौक्योर कर रहे हैं । जबतक दानों ट्रांसफार्मर नहीं आयेंगें वहाँ का समाधान नहीं हो पायेगा वहाँ पर अभी पीक लोड 580 एम्पीयर का है और हमारे पास इस समय क्षमता 380 एम्पीयर का है जिसके कारण प्रौब्लेम है और दूसरे जगह प्रौब्लेम डिस्ट्रीव्यूट किया है । 5-5 मेगावाट का दो ट्रांसफार्मर प्रोक्योर करके इस काम को करेंगें। थोड़ी सी परेशानी है, मुक्ति मिलेगी । सरकार सजग है कि बिजली कैसे दें । महोदय, मैं फिर कह रहा हूँ कि विपत्ति को मिलकर झेलनी पड़ती है, लड़ने से विपत्ति दूर नहीं होती है और हमें ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा । महोदय, मैं फिर कह रहा हूँ कि पाँच पाँच मेगावाट का ट्रांसफार्मर दूर से आ रहा है । आने दीजिए, महोदय, हम तत्काल लगायेंगें । यदि आज कह दूँ कि 5 दिन में और

किसी कारण से उसमें दो दिन की देरी हो जायेगी तो फिर हमारी नीयत पर संदेह आ जायेगी । तीन-तीन मेगावाट का ट्रांसफार्मर देकर हमने समस्या का हल किया है अस्थायी रूप से और 5-5 मेगावाट का दो ट्रांसफार्मर देकर स्थायी रूप से समस्या को हल करेंगे ।

श्री राधा कृष्ण किशोर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके तरफ से मुझे बोलने का निर्देश हुआ है लेकिन मुझे सूचना मिली है कि हमारे दल के मुख्य सचेतक फुरकान अंसारी साहेब ने श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह जी का नाम दिया है तो मेरे दल की तरफ से श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह जी बोलेंगे ।

श्री मुंशीलाल राय : महोदय, विजय बाबू जितनी बार मेरे यहां गये, मैंने न सिर्फ उनकी बात सुनी, बल्कि कार्रवाई का आदेश भी दिया । इधर आकर फिलहाल हमने जांच करने की कोशिश की और अभी चीफ इंजीनियर को यह कहा था कि विजय बाबू के क्षेत्र में दियारे के इलाके में चापाकल नहीं लगने की शिकायत मुझे मिली है, खुद उन्होंने आकर कहा है, इसलिये जांच करके दीजिये कि कौन दोषी है, जिसके चलते चापाकल नहीं लगा । उन पर कार्रवाई करेंगे । इसकी रिपोर्ट पर ही, हमने कोई जांच अपने नहीं कराया ।

(व्यवधान)

जितनी बार कहा इन्होंने, जो भी कहा, न सुनने का तो सवाल ही नहीं है, पानी किसी दल विशेष का नहीं है, वे मित्र भी हैं हमारे । यह दल विशेष की बात नहीं है ।

महोदय, हमने 400 घरों में फैसला किया, जो एम0एल0ए0 हैं, एम0एल0सी0 हैं, जहां पानी नहीं मिलता है, उसमें अलग से प्रोवीजन करके, दल विशेष की बात नहीं, चार सौ चापाकल नहीं कर सकते हैं तो बोरिंग कर दीजिये, जहां माननीय सदस्य रहते हैं । इनके दानापुर शहर के बारे में बतावें, जहां ये रहते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री मुंशीलाल राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूँ, विजय बाबू अगर इन्कार कर देंगे तो मैं मान लूँगा, वे यहां बैठे हुए हैं । आपको गलतबयानी समझ में नहीं आयेगी । विजय बाबू कह दें कि इनको कभी कम सम्मान दिया हो, कभी इनके कहने पर जांच करने के लिये नहीं कहा । अभी तो चीफ इंजीनियर को दिया है, इनके कहने पर और जहां तक दानापुर शहर है, विजय बाबू दानापुर के बारे में विधायक लोगों को एक बात जानना चाहिये कि शहरी पानी भी सरकार ही देती है, लेकिन विभाग दूसरा रहता है । तो आप धरना पर मेरे खिलाफ बैठ जाते हैं, बिना वजह भी बैठ जाते हैं । बगल में श्री नारायण बाबू हैं, उनके खिलाफ तो आप बैठते नहीं हैं ।

(व्यवधान)

और फिर हमलोगों ने यह कहा है कि जहां एक जगह बोरिंग फेल हुआ ।

श्री विजय सिंह यादव : महोदय, मंत्री महोदय दानापुर शहरी क्षेत्र में 100 घरों में आग लग गयी, उसके बारे में क्या कहेंगे ? आज तक हमने आग्रह किया, चापाकल नहीं गड़ा ।

श्री मुंशीलाल राय : महोदय, हमलोगों ने आदेश दिया है । मुख्यमंत्री जानेवाली थीं, वहां जाने का रास्ता बन्द हो गया है ।

(व्यवधान)

जरा सुन लीजिये, एक मिनट ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विजय सिंह यादव जी, अब यह समाप्त है । श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह । अब श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह बोलेंगे । ये 52 घंटे अनशन करके इसीलिये आये ।

(व्यवधान)

नहीं यह प्रश्न अब नहीं उठेगा । गलतबयानी कुछ नहीं हुआ ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा विभाग के द्वारा जो बजट पेश हुआ है, उस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय मंत्रीजी का जो प्रतिवेदन है, जिसमें राज्यमंत्री हैं, सचिव हैं बहुत चालाकी के साथ ऊर्जा विभाग का प्रतिवेदन रखा है । इसमें लिखा है कि – "बिहार में विद्युत प्रक्षेत्र का विकास यहां की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुपात में आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं हो पाया है । यह विदित है कि बिहार में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रारंभ में विद्युत प्रक्षेत्र प्रगतिशील रहा परंतु कालांतर में बढ़ती हुई आबादी के विरूद्ध बिजली की मांग को पूरा करने में अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ा ।"

उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी परियोजनाएं बनी, चाहे वह डी0वी0सी0 हो, चंद्रपुरा, बोकारो थर्मल हो, बिहार सरकार का, बरौनी, कांटी, पतरातू हो या तेनुघाट हो, यह सब पहले की परियोजनाएं हैं और कांग्रेस की यह सब देन है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जितनी भी बिजली उत्पादन करने की क्षमता है, उसका सही ढंग से रख-रखाव नहीं हो रहा है, जिसके चलते उत्पादन नहीं हो रहा है और उत्पादन जो नहीं हो रहा है, इसके चलते पूरे बिहार में जितनी बिजली चाहिए थी, कल-कारखानों के लिए, किसानों के लिए और इस बिहार की जनता के लिए, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आज हम किसी के उपर दोष लगा दें, महोदय कोयला के बारे में चर्चा होती है, महोदय मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बिजली विभाग के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। महोदय, एक आँकड़ा के बारे में, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की जो स्थिति है, उसको आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं । महोदय, आज जो कोयला की बात होती है, आज बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एक करोड़ के घाटे की बात कर रहा है, महोदय, इनके यहाँ कोयला जाता है, वेरमो कोलफील्ड से और हजारीबाग कोलफील्ड से । महोदय, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स 2 रूपया 42 पैसा देती है और विद्युत बोर्ड का खर्च तीन रूपया 45 पैसा का होता है, महोदय, आप सोच सकते हैं कि तेनुघाट की क्या स्थिति होगी ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहूंगा कि आप इसकी जांच

कराइये । माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव में तेनुघाट की बात कर रहे थे, महोदय, यहाँ पर जान-बूझकर रेल सेवा को नहीं बनाया जा रहा है, वहाँ पर लॉ एण्ड ऑर्डर की बात होती है । महोदय, आज गिरिडीह से कोयला बरौनी थर्मल और कॉटी थर्मल में आता है और कहा जाता है कि कोयला खराब है। उपाध्यक्ष महोदय, हम इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं । महोदय, बहुत से माननीय सदस्य कह रहे थे कि नेपाल से बिजली लिया ज़ाय । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि आज दामोदर भैली कॉरपोरेशन, जो 1948 में बना है, बिहार और बंगाल दानों के सहयोग से बना है, आज उसके सामने समस्या है कि वह बिजली कहाँ बेचें । महोदय, दामोदर भैली कॉरपोरेशन के चेंयरमैन कह रहे हैं कि हमारे पास समस्या है कि हम 200 मेगावाट बिजली कहाँ बेचे । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि बहुत जगह ट्रान्समिशन लाइन नहीं बना है । महोदय, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत जगह आपका ट्रान्समिशन लाइन है, जैसे बोकारो है, हजारीबाग है, गिरिडीह है, लोहरदग्गा है, धनबाद है, वहाँ पर भी सी0सी0एल0 और वी0सी0सी0एल0 है, वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ पर खेती करने का साधन है, सब्जी का रामगढ़ में काफ़ी अच्छी खेती होती है, यह आप भी जानते हैं, लेकिन महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि उनलोगों को भी पर्याप्त मात्रा में बिजली हम नहीं दे पाते हैं । आज ट्रान्समिशन लाइन की वहाँ पर कोई कमी नहीं है, यह तो सिर्फ इनका बहाना है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को बताना चाहते हैं कि आप स्पेशल बैठक बुलाइये, छोटानागपुर संथालपरगना के लोगों की और वहाँ पर पर्याप्त बिजली देने का विचार करें । उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्रपुरा जैसा प्लांट, बोकारो का थर्मल ए और बी, पतरातू थर्मल का बिजली, डा0भी0सी0 का बिजली है, उसके बाबजूद वहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पाती है, यह हमारा फेल्योर है, इसको आपको मंत्री जी मानना पड़ेगा । उपाध्यक्ष महोदय, उसीतरह से पनबिजली की हालत है । महोदय, मैथन की बात आती है, चाहे दूसरे जगहों का बात आती है, आप शिमला की बात करते हैं, वहाँ 18 हजार मेगावाट बिजली जलबिजली से पैदा होता है, उतनी क्षमता हमारा बिहार भी कर

सकता है, अगर यहाँ की सरकार पनबिजली पर ध्यान दे तो । उपाध्यक्ष महोदय, शिमला में जितनी मेगावाट पनबिजली से बिजली पैदा होता है, उतना हम भी पैदा कर सकते है, बशर्ते की सरकार उसपर ध्यान दें ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देवघर में श्रावणी मेला लगा हुआ है, वहाँ पर बिजली का उपाय सरकार द्वारा किया गया है । लेकिन जैसे ही मेला समाप्त होगा, वहां की क्या स्थिति हो जायेगा । गिरिडीह में एक जगह है जहां से साढ़े आठ सौ करोड़ रूपए का राजस्व मिलता है सेंट्रल कोल फिल्ड, बी0सी0सी0एल0 और ई0सी0सी0एल0 से लेकिन वहां बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते हैं । कैपटिव पावर प्लांट बना । उससे बिजली का उत्पादन भी हो रहा है और ग्रीड को बिजली दिया लेकिन आज बिजली लेने वाला नहीं है । सौर ऊर्जा के बारे में एक माननीय सदस्य बोल रहे थे जो बैठ गया है । ट्रांसफार्मर आज कहीं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं । हरिजनों को बिजली नहीं दे रहे हैं । सारा प्रोग्राम बंद हो गया है । ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए केन्द्र से जो पैसा आता है, उसका बंदरबांट हो रहा है ।

इसलिए मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि इसमें ध्यान देकर निश्चित तौर से इनक्वायरी कराइये और देहात में विद्युतीकरण करवाइये ।

श्री विद्या सागर निषाद : उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग द्वारा सरकार का जो बजट आया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

अभी हमारे माननीय विरोध दल के सदस्यों ने बिजली के संबंध में बहुत सी बातें रखी और उनलोगों ने खामियां ही दिखाया है लेकिन सरकार गरीबों और दलितों के बीच बिजली पहुंचाने का जो काम कर रही है, उस संबंध में उनलोगों ने एक बार भी चर्चा नहीं की । बड़े लोगों की बात तो आई । पावर ही नहीं रहेगा तो हमारी शक्ति नहीं बनेगी और दूसरे प्रोविंस जहां छोटे-छोटे उद्योग में बिजली लगे हुए हैं, जहां छोटे-छोटे लोगों को काम में लगाने की बात आई, वह राज्य आगे बढ़ा । बड़े कराखाने और बड़े पावर की बात हुई लेकिन गांव में कैसे बिजली दी जाये, इसपर हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने

सदन के माध्यम से सरकार को कोई सुझाव नहीं दिया बल्कि उस ओर मुखातिब न होकर उनकी खामियों की ओर ही मुखतिव हुए । मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि जो छोटे-छोटे गांव, देहात हैं, वहां समुचित रूप से बिजली की व्यवस्था की जाये । जहां किसान पम्पिंग सेट के माध्यम से खेती करते हैं, जहां किसानों की ज्यादा पूंजी लगती है और उससे किसान परेशान रहते हैं, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार छोटे-छोटे गांवों में बिजली पहुंचाये ।

जहां तक बिजली का सवाल है, तो सबसे ज्यादा बड़े लोग बिजली की चोरी करते हैं और यदि गरीब लोग बिजली लगा हैं तो उनके विरूद्ध तरह-तरह की बात आती है । अगर बिजली की चारी रोकी जाये तो हमारे राज्य में बिजली की दिक्कत नहीं होगी । अगर छोटे-छोटे कारखाने में बिजली लगी हुई है तो वहां दो मीटर रहता है एक मीटर यों ही लगा रहता है और दूसरे मीटर के माध्यम से वह कारखाना चलाता है और वहां बहुत ज्यादा बिजली की चोरी होती है । इस प्रकार की बिजली की चोरी को रोका जाये ताकि अच्छी तरह से बिजली का उपयोग हो सके ।

कुटीर उद्योग में छोटे लोग, गरीब लोगों के लिए बिजली की व्यवस्था है। इसके लिए कम पैसे पर गांवों में बिजली दी जाये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गरीब लोग काम कर सके और अपनी उद्योग स्थापित कर सकें । पूर्व में श्री लालू यादव की सरकार थी और आज श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार है। आज अधिक राजस्व की वसूली हुई है । विगत पांच-छः वर्षो में सवा गुणा, डेढ़ गुणा ज्यादा राजस्व की वसूली हुई है और उसके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं । हम यह भी देख रहे है कि जहाँ-जहाँ गांवों में बिजली नहीं थी, जिस गांव के लोग अंधकार में रहते थे वहां भी आज बिजली देने का काम किया जा रहा है । मैं आप के माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि ज्यादा तेज़ी से हम वहां कैसे बिजली पहुंचावें, छोटे-छोटे रोज़गार करनेवाले जैसे कहीं पर मोटर का लेथ मशीन चल रहा है, कहीं पर तेल पेरने की मशीन चल रही है हम वहाँ पर कैसे बिजली दे सकें इस पर विचार करने की बात है । क्योंकि

जबतक हम छोटे–छोटे उद्योगों को बिजली देने का काम नहीं करेंगें, बिजली के अभाव में हम बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते हैं ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जल–विद्युत की ओर ले जाना चाहता हूं । महोदय, मेरे राज्य में पानी सबसे ज्यादा हैं । इससे हम बहुत ज्यादा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और पानी से बिजली का जो उत्पादन होता है वह सस्ता पड़ता है । लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार का कुछ ऐसा निगाह हमारे राज्य पर रहा कि बिजली के मामले में हम पीछे रह गये । कोयला के माध्यम से जो बिजली का उत्पादन होता है, वह काफी मंहगा पड़ रहा है । हमारे यहां पानी का स्टॉक है । गंगा का पानी, कोशी का पानी, बागमती और गंड्क का पानी है । इन सारे पानी से सिंचाई के साथ–साथ बिजली का भी उत्पादन किया जा सकता था । लेकिन भारत सरकार की निगाह इस रूप में रही है कि जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए था उतना आगे नहीं बढ़ पाये हैं । हमारे प्रति केन्द्र सरकार की हमेशा द्वेष की भावना रही है।

महोदय, दरअसल कोयला भारत सरकार के माध्यम से है और भारत सरकार के माध्यम से होने के कारण आज वह कोयला मुझे जिस रूप में चाहिए वह नहीं मिल रहा है । कोयला के संबंध में माननीय सदस्यों ने कहा लेकिन मैं कोयला के संबंध में कहना चाहता हूं कि कोयला ट्रक से ले जाया जाता है जिस कारण वह ज्यादा मंहगा पड़ता है । लेकिन हम वह कोयला रेल द्वारा ले जायेगें तो वह कोयला कम भाव में पड़ेगा ।

श्री दिलीप वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ इन्फॉरमेशन है । प्वांयट ऑप इन्फोरमेशन यह है कि माननीय सदस्य ने अपने भाषण के क्रम में कहा है कि कोयला भारत सरकार की चीज हैं, पानी से बिजली का उत्पादन सस्ता पड़ता है । मैं यह आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कौन सी योजना राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजी है जिसको भारत सरकार ने अस्वीकृत कर दिया है । यह मैं जानना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सरकार इस को बतावेगी ।

श्री विद्या सागर निषाद : महोदय, मैं एक सदस्य की हैसियत से बोल रहा हूँ और सरकार द्वारा क्या काम किया गया है, उन के संबंध में सरकार जबाब देगी। मैं अपनी बात को सदन के सामने रख रहा हूँ । महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां बड़ी-बड़ी चीजें हैं जो पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, लेकिन बिहार के अंदर है और बिहार के अंदर होने के कारण एक जगह सीमित हो गया है । सारी चीजें हमारे पास है, हमारे पास कोयला है, हमारे पास लोहा है, हमारे पास मजदूर हैं, हमारे पास ताकत हैं । इन सारी चीजों के रहने के बावजूद हमारे यहॉ पावर नहीं है । आज पंजाव में पावर है लेकिन वहां लोहा हमारा है । जहां से थ्रेसर मशीन बन कर आता है, और कहां से बन कर आता है ? हरियाणा से आता है । आज ट्रैक्टर कहां से आता है ? सारी किसानों के उपयोग में आनेवाली चीजे जो पावर से वहां बनती हैं । हमारे यहां नहीं बन पा रही है । क्यों नहीं बन पा रही है ? पावर की कमी के कारण नहीं बन पा रही है । यह सबसे बड़ा दोष है जो बिहार सरकार का नहीं बल्कि भारत सरकार का दोष है । भारत सरकार सब दिन द्वेष की भावना से इस राज्य को देखती रही है । और देख करके चाहा कि इस राज्य के मजदूर और गरीब लोग किसी तरह से आगे नहीं बढ़ें । महोदय, जिसकी वजह से आज हमारे राज्य की यह स्थिति है । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि सबसे ज्यादा कृषि के मामले में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बिजली की सबसे ज्यादा खपत हो, छोटे-छोटे उद्योगों में बिजली की खपत हो ताकि गॉव में रहने वाले गरीब लोगों को रोजी मिल सके । महोदय, यह पावर का सही उपयोग होगा और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं । महोदय, मैंने अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में तारांकित प्रश्न भी किया था लेकिन संयोग से आगे नहीं आया । महोदय, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहॉ के लिए दो-तीन वर्ष पहले अपने क्षेत्र के अन्दर बिजली के लिये लोगों से रूपया जमा करवाया, जैसे- बोरियासी, करजतवा,

गौरैया बथान, आदि 5-6 जगहों का काफी पैसा जमा किया गया लेकिन कुछ पदाधिकारियों का ऐसा रवैया रहा जिसकी वजह से आज तक उनको बिजली नहीं मिल पायी है । मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय की ओर से इसके संबंध में, चाहे जो भी पदाधिकारी इसके लिए दोषी हों, कार्रवाई हो । महोदय, हमारा परबत्ता और गोगरी खगड़िया जिला में है, मंत्री जी इस ओर भी निगाह करते हुए, हमारा क्षेत्र जो कृषि के मामले में सबसे आगे है, हमारे क्षेत्र में सरकार भरपूर बिजली दें ।

महोदय, सरकार का काम उतना संतोषप्रद तो नहीं है लेकिन इस सरकार ने काफी संतोषजनक काम किया है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ । महोदय, आज की दुनिया जिस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर जोर दे रही है और जिस मामले में सबसे अधिक चिन्तित है, आज की सभ्यता, आज की संस्कृति, आज के इन्सान के जीवन का रहन-सहन और यहाँ तक कि जीना भी विद्युत और उर्जा के बिना सम्भव नहीं है, उस विषय पर आज चर्चा हो रही है, जिसके बिना जिन्दगी की कल्पना नहीं की जा सकती है ।

महोदय, आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर बिहार की इस सर्वोच्च संस्था में चर्चा के दौरान में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, उर्जा के मामले में कितने संजीदा हमलोग हैं, मैं बड़े ही गम्भीरता और दुःखी मन से कह रहा हूँ । महोदय, इस बिहार के विकास के प्रति हम जितने चिन्तित नहीं हैं, उससे अधिक चिन्ता हमें छोटी-छोटी बातों के लिए है । लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य छोटी-छोटी बातों में उलझकर बहस में नहीं शिरकता करें और सरकार भी भड़काऊ-तड़काऊ ढ़ंग से, तीव्र बुद्धि के प्रयोग से तथा चतुराई का सहारा लेकर आँकड़ों के मायाजाल में वास्तविकता को अवास्तविकता ओर अवास्तविकता को वास्तविकता

में बदलने का प्रयास नहीं करें । आप ऐसा कर तो सकते हैं लेकिन सच्चाई से मुँह नहीं छिपा सकते हैं ।

श्री जगदानंद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है, सरकार का जवाब भी होना है इसलिए माननीय सदस्यों को बिन्दुवार बात कहनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में अपनी बातों को कहें चूंकि समय कम है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं दो-तीन बातों के बारे में कहना चाहता हूँ । महोदय, आज भी बहुत चतुराई से सरकार जवाब देगी । महोदय, पिछला इतिहास रहा है कि आँकड़ों के शानदार निर्माण से, कंपरेटिव स्टेटमेंट से बातों को रखेगी सरकार, लेकिन इतिहास से रिसर्च का विषय हो सकता है, अमुक राज्य में ऐसा हुआ, मेरे राज्य में ऐसा हुआ लेकिन सचमुच में बिहार की 9 करोड़ जनता की भलाई के लिए वास्तविकता को स्वीकार करके कि हम कहाँ खड़ा हैं, कहाँ क्या करना चाहते हैं, इन सब बिन्दुओं पर आधारित बहस हम जबतक नहीं करेंगे और इसका समुचित उत्तर नहीं होगा तबतक हम इस बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं ।

महोदय, उर्जा का जो बजट है, उर्जा दो भागों में विभक्त है, एक पारम्परिक उर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है । महोदय, समुद्र के लहरों से बिजली पैदा करना और महोदय, सोलर इनर्जी के सबसे नये तकनीक पर जोर दिया जा रहा है । आज दुनियाँ ने जो सबसे ज्यादा विकास का मामला अपनाया है, वह है सोलर इनर्जी और महोदय, प्रकृति ने जो हमें भूगोल बख्शा है, हम निश्चित रूप से ....

श्री लाल बाबू प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा हूँ। मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर यह है कि माननीय सदस्य उर्जा मंत्री बिहार के थे तो क्या इनकी थीसीस, फिलोसिपी, इनकी सारी साजिश, इनकी सारी अकलमंदी, इनकी सारी विद्वता 12 बजे रात कोशिश करने के बाद कहाँ चली गयी । इनके समय में उर्जा की क्या स्थिति थी, यह बतायें ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय राज्य मंत्री लाल बाबू प्रसाद जी, मैं आपकी बातों का जबाब देने की आवश्यता नहीं समझता हूँ । महोदय, मैं कह रहा था कि सोलर इनर्जी, वींड इनर्जी, आज हम बिहार के मामले में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, इसपर धन आवंटित किया जाना चाहिए । महोदय, जहाँ-तक अन्य बातों का सवाल है, भारत सरकार ने भी सबसे कम इनभेष्टमेंट इस राज्य के लिए और बिहार सरकार ने भी सबसे कम इनभेष्टमेंट इस सेक्टर में किया है बल्कि जो लोग आज पीठ थप-थपा कर बात कह रहे हैं ।

महोदय, प्रश्न पंचवर्षीय योजना में बिहार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि कोई निवेश ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार में हुआ ही नहीं । द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में थोड़ा बहुत हुआ लेकिन इसके बाद फिर कलान्तर में, केवल हम जो बस्तुस्थिति है, जो रियलिटी है, उसी पर जीने का आदी हूँ । कोई विकास के मामले में कोई ध्यान नहीं दिया गया । आज भी सरकार चार अरब से अधिक का बजट पेश करते हुए लम्बे इरादे का इजहार करते हुए बजट पेश कर रही है । मुझे नहीं पता है जो आकलन रिसोर्सेस के मामले में, प्राप्ति के मामले में भारत सरकार के भरोसे या आपने रिसोर्सेस मोवलाइजेशन के बारे में कल क्या स्थिति होगी, प्लांट का साइज कितना रहेगा, क्योंकि पिछला अनुभव यही रहा है कि लम्बे-लम्बे वायदे किये जाते रहे हैं । बजट में एलौकेशन करते हैं लेकिन रियलीटी में बिल्कुल विपरित निगेटिभ बोला जाता है । अगर ज्यादा हम इस सेक्टर में खर्च नहीं करेंगें । तो बिहार की जो स्थिति है, वह स्थिति और भी भयावह होनेवाली है । साउथ बिहार के लोग चिला-चिला कर कहते हैं, आज वहाँ ऊर्जा का सबसे ज्यादा सेक्टर है । महोदय, अगर बिहार में बिजली की टोटलिटी को जोड़ा जाय तो 00 परसेंट इनभेस्टमेंट साउथ-बिहार में हुआ है, नोर्थ और मध्य जीरो पर खड़ा है । भारत सरकार के जो आंकड़े हैं, उसको भी सही करने की आवश्यकता है । इस्टर्न रीजन में 6.6 परसेंट अभी तक इनभेस्टमेंट हुआ है और बिहार में केवल 0.6 परसेंट इनभेस्टमेंट है । केवल पहली और अंतिम यूनिट भारत सरकार का कहलगांव है । महोदय, उसी तरह

से ट्रांसमीशन के सेक्टर में भी यही स्थिति है । महोदय, मंत्रीमंडल में एक मंत्री कितना ही सक्षम क्यों न हो, उसका कितना भी डीटरमीनेसन हो, उससे हालात नहीं सुधर सकते हैं जबतक कि कैबिनेट में कम्पलीट कौओडीनेशन न हो, पूरे मंत्रिमंडल के मुखिया का, पूरे का इरादा बिजली के प्रति, ऊर्जा के प्रति चेतनशील नहीं होगा, राजनीति से मामले को ऊपर नहीं रखा जायेगा तबतक ऊर्जा के क्षेत्र में विकास संभव नहीं है ।

महोदय, महाराष्ट्र में या बगल के राज्य बंगाल को ले लें, पिछले 15 सालों से एक ही व्यक्ति ऊर्जा मंत्री हैं, चेयरमेन भी आठ वर्षो से कम कोई नहीं रहे हैं । आप चले जाइए पंजाब में 13 साल से एक ही व्यक्ति विद्युत बोर्ड के चेयरमेन हैं, उसी प्रकार राजस्थान में भी हैं । लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंट चेंजेज होता रहता है । कभी कोई पावर सेकेट्री और कभी कोई चेयरमेन, कभी कोई पावर मिनिस्ट्रर ? महोदय, इस तरह से जब इस्टुमेंट में पोलिटिकलाइज़ किया जायेगा, मैं बार-बार सदन में निवेदन करता रहा हूँ कि सम्पूर्ण राजनीति भेद-भाव से उपर उठकर अगर बिहार में एग्रीक्लचर ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्सन को बढ़ाना चाहते है इंडस्ट्रीज ग्रोथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एरीगेशनल पोटेंसियल को क्रिएट करना चाहते हैं तो राजनीति से उपर उठकर हमें सोचना होगा; हमें देखना होगा कि कौन व्यक्ति बोर्ड के चेयरमेन हो रहे हैं, किस जात का हो रहे हैं, किस बिरादरी का हो रहे हैं, यह हमें नहीं देखना होगा ।

श्री नवीन किशोर प्र० सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ इनफॉरमेशन पर हूं.......

उपाध्यक्ष : पहले मैं माननीय मंत्री श्री मुंशी लाल राय जी का नाम पुकार लिया हूं, इसलिए आप बैठिये ।

श्री मुंशी लाल राय : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया तुरंत-तुरंत, फ्रीकवेन्टली बदला जाता है । 5 साल तक माननीय सदस्य इस प्रदेश के उर्जा मंत्री थे । एक बात बोलने के क्रम में ये बताये कि कितने गांव में एक

गांव का भी नाम बतायें । किसी गांव का इनके नहीं बदलने पर ग्रामीण विद्युतीकारण किया गया, ये बतावें चूंकि ये गांव से आते हैं और जगह का तो छोड़ दीजिए, सुपौल जिला का ही बता दें ।

श्री विजेन्द्र प्र० यादव : महाशय, ठीक है-ठीक है, बहुत धन्यवाद ।

श्री मुंशी लाल राय : उपाध्यक्ष महोदय, गोबर-गणेश 5 साल तक रहे या 20 साल तक रहे, कुछ होने वाला नहीं है ।

श्री विजेन्द्र प्र० यादव : बहुत धन्यवाद । श्री मुंशी लाल राय जी की प्रतीभा को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उनकी समझदारी का मुझे पता है । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप 90 से लेकर आज तक सारे उर्जा का विकास और उनके संरक्षण, उनकी सारी चीजों को पढ़ें । बिना पढ़े कोई इन्सान अगर कभी-कभी किसी बातों पर इन्टरफेयर करता है तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है और किसी जानने वाले और समझदार व्यक्ति के लिए भी उत्तर देना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं उनका उत्तर देना उचित नहीं समझता हूं ।

इसलिए महोदय, मैं कह रहा था, निश्चित तौर से राजनीति से हट करके, राजनीति से ऊपर उठ करके और बिजली के मामले में एक नया खोज विकसित करना चाहिए । मैं आपके माध्यम से सदन से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि केवल बजट में दो-तीन घंटा भाषण से काम नहीं चलेगा, एक रोज स्पेशल डिवेट, बिहार का विकास और विकास का मतलब होता है इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है उर्जा, इसलिए एक रोज स्पेशल डिवेट बिहार के विकास पर होना चाहिए और बिहार कैसे विकसित होगा ? जब तक उर्जा का विकास नहीं होगा, तब तक न बिहार में इन्डस्ट्रीयल ग्रौथ बढ़ेगा, न इरीमेशन का प्रोटेन्सियल हम क्रियट कर सकते हैं, न हम कुदरत ने जो दिया है, उसकी हम उपयोग कर सकते हैं और न बिहार जिन्दा रह सकता है । इसके बात महोदय, एक निवेदन और कहना चाहता हूं सदन से और सरकार के साथ-साथ, विपक्ष के सभी नेताओं से भी कृपया करे कोशी के मामले में, आज नेपाल प्रोटेन्सिसयल प्रोजेक्ट कर रहा है एक लाख से अधिक हाइड्रो-इलेक्ट्रीक

का । आज का दुनिया का सबसे चीपेस्ट इलेक्ट्रीसीटी, उसमें कन्स्ट्रक्शन कोस्ट जरूर लगता है ज्यादा लेकिन सबसे चीपेस्ट इनर्जी और उसमें भी कोशी, जो हमारे यहां विकराल नदी के नाम से जानी जाती है । सबसे ज्यादा 14 हजार मेगावाट वेस लोड की क्षमता वाली है लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री उस समय थे दूसरे जगह के और उत्तर प्रदेश के दबाव से पंचेशरी का समझौता हो गया । आज इतफाक से बिहार के धरती पर जन्मा हुआ इन्सान ही नेपाल का प्रधानमंत्री है । मैं अनुरोध करूंगा बिहार सरकार के मंत्री से और मंत्रिमंडल से कि वे भारत सरकार पर दबाव डालकर के अपने हैसियत और अपने अधिकार का प्रयोग करके बिहार के जनता के हित में और सारे माननीय विरोधी दल के नेता मिलकर के कोशी हाईडल के मामले में एक नये विकास के साथ भारत सरकार पर दबाव डाला जाय कि कोशी हाईडल योजना को अविलम्व कार्यान्वित किया जाय ताकि न सिर्फ बिहार, सम्पूर्ण उत्तर भारत इनक्लडिंग बंगलादेश को भी हम पावर सप्लाई कर सकते हैं और जिस दिन यह तो जायेगा, इतिहास का एक नया अध्याय का शुरूआत होगा और सबसे चीपेस्ट बिजली हमें मिलेगी । दुनिया आज दौलत लेकर खड़ी, पैसे की कोई समस्या नहीं है केवल हम अपने हैरत को, अपने हड्तस को जो भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच में है, सार्क देश का वो भी सदस्य है, इसलिए बहुत बड़ी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा । आज अगर हम यह ऑपरेशन क्रियट करें तो यह काम हो सकता है । फिर मैं अन्त में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सच्चाई को कबूल करें और वास्तविकता को कबूल करें और कुतर्कों को तर्क से, चतुराई से आप वास्तविकता को न ढंके और अपना सदुपयोग, अपने ताकत का प्रयोग भारत सरकार पर दबाव डालकर के इस बिहार में आने वाले वर्षों में विकास के मामले में, अगर हम विकास करना चाहते हैं, बिहार को जिन्दा रखना चाहते हैं उर्जा के मामले में नयी सोच और नई विचार-धारा का प्रतिपादन किया जाना चाहिए । इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामलाल सिंह जी, 5 मिनट में आप अपनी समाप्त करें ।

श्री राम लाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । उपाध्यक्ष महोदय, 23 मार्च 1998 को वित्त मंत्री ने जो भाषण किया था इस सदन में, उसके अनुसार हम कुछ आंकड़ा पेश करना चाहता हूं ।

उन्होंने कहा था कि 1996-97 में 1010 करोड़ रूपये का अनुमानित लागत 5580 योजना का बनायी गयी थी जिसमें कि यह कहा गया था कि 31 हजार 7 सौ गांव, नये गांव का विद्युतिकरण किया जाएगा और 1600 गांव जो पुराने गांवों का विद्युतिकरण किया गया था, पहले जिसमें ट्रांसफॉर्मर, पोल, तार या दैविक प्रकोप से खराब हो गया, बरबाद हो गया, उसे बदल कर पुनर्जीवित किया जाएगा, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आपने जो बजट 1010 करोड़ रूपये का जो अनुमानित लागत से जो बनाया था 1996 ई0 में, तो इन गांवों का विद्युतिकरण करने के लिए और पुनः ट्रांसफॅर्मर चेंज करने के लिए, तो कितना कर पाए हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां इनका बजट 1994-95 में 4 अरब 88 करोड़ 86 लाख था और 1996-97 में 3 अरब 78 करोड़ 89 लाख हो गया, यानी घट गया और 1998-99 में 4 अरब 38 करोड़ 27 लाख 86 हजार रूपये है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 1994-95 में जो 4 अरब 88 करोड़ रूपये का बजट था जो घट कर 4अरब 38 करोड़ हो गया इनका बजट और योजना मद में 2 अरब 16 करोड़ रूपया है और गैर-योजना मद में 2 अरब 22 करोड़ है, यानि योजना मद से गैर-योजना मद में बजट ज्यादा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रख-रखाव पर और इस्टैब्लिशमेंट में ज्यादा जोर दे रहे हैं और कोई भी योजना लेने के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यू0पी0 में हाइडल-इलेक्ट्रीसीटी से 1504 और थर्मल से 4570-टोटल 6074 होता है । महाराष्ट्र में 1780 हाइडल से और थर्मल से 8247-टोटल 10 हजार 27, पश्चिम बंगाल में हाइडल से 96 और थर्मल से 3478-टोटल 3576, और हमारे बिहार का क्या है- 164 है हाइडल से क्षमता का और थर्मल 1603 यानी 1000 मेगावाट मिल रहा है अर्थात 33 परसेंट कम

रहा । मैं कहना चाहता हूं सदन के सामने कि जो इनकी क्षमता है उसके मुताबिक बिजली का उत्पादन नहीं होता है, कम मिलता है । इसलिए बिहार की यह दु:स्थिति हैं ।

महोदय, मैं, जहां तक विद्युत ट्रांसमीशन बना हुआ है जो कि फतुहा में राजेन्द्र सेतु में है, ग्रीड ठीक नहीं कीजिएगा, उसको पूरा नहीं कीजिएगा तो सम्पूर्ण बिहार में बिजली की आपूर्त्ति नहीं हो सकती है और बिहार के विकास का काम नहीं हो सकता है, चूंकि विद्युत पर ही पूरा देश का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का विकास संभव है । उद्योग लगाए जा सकते हैं, खेती-बारी का काम हो सकता है या ट्यूववेल लगाये जा सकते हैं, मशीन बैठाये जा सकते हैं, पूरे राज्य में विकास का काम तभी हो सकता है जब पूरे राज्य की विद्युत दिला सकते हैं । जहां तक मुझे जानकारी है, अभी मैं अपने क्षेत्र की बात बतलाना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी मेरे क्षेत्र-कैमूर जिला से आते हैं । मैं तो चाहूंगा कि जो भी मंत्री होते हैं वे अपने जिला के लिए विशेष रूप से करते हैं । माननीय मंत्री महोदय से मैं चाहूंगा कि वे भी भभुआ की तरफ ध्यान दें । मैंने पिछली बार भी सदन में जो ध्यानाकर्षण दिया था विद्युत बोर्ड में एक नियम बना है कि जो 75फीसदी 80,फीसदी विद्युत बकाया जमा कर देगा, उसको ट्रांसफॉर्मर दे दिया जाएगा । लेकिन मैं चाहता हूं कि कैमूर जिला के वार्ड-11, वार्ड-6 राधानगर में 100 परसेंट बिजली का बकाया पूरा हो गया है । इस ट्रान्सफार्मर पर जितना बकाया था, उसका १०० प्रतिशत दे दिया गया । भभुआ शहर है और भभुआ शहर के लोग पैसा दे चुके है, राधा नगर में दे चुके हैं, भगवानपुर के रामगढ़ में ८० प्रतिशत् लोग पैसा दे चुके हैं, इस तरह से बहुत गांव हैं, अखलाश्पुर में ७५ प्रतिशत् पैसा दे चुके हैं लेकिन बिजली की आपूर्त्ति अभी तक नहीं की जा सकी है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि इन गांव में ट्रान्सफार्मर लगाया जाए । दूसरी मांग मैं यह करना चाहता हूं कि ५,६,७ सालों से ट्रान्सफार्मर बैठाने के लिए एग्रीमेन्ट करके रखे हुए हैं, पैसा जमा करके रखे हुए हैं लेकिन अभी इन ग्रामों में जैसे मरर्च, डुमडुम आदि में ट्रान्सफार्मर, तार, पोल आदि की आवश्यकता है, ६ सालों से किसान, दर्जनों

किसान एग्रीमेन्ट कर चुके हैं लेकिन वहां विद्युत् की आपूर्त्ति नहीं की गयी है। मैंने बहुत जोर लगाया है तो कुछ सामान भेजा गया है लेकिन अभी तक चालू नहीं किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि चैनपुर प्रखंड में वारन सब स्टेशन लगाने की आवश्यकता है । हमारे कैमूर में तीन सौ फीट से पानी गिरता है, वहां पर पन बिजली प्लान्ट लगाने की आवश्यकता है, जब तक पन बिजली प्लान्ट नहीं लगेगा तब तक बिजली की समस्या का हल नहीं हो सकता है, कम पैसा पर बिजली का उत्पाद किया जा सकता है । तेलहा कुंड का १९९६ में सर्वे करने के लिए मैकन को दिया गया, इस बात को जगदा बाबू भी जानते हैं, लेकिन उसका सर्वे के बाद क्या हुआ, कुछ पता नहीं है, इसलिए तेलहा कुंड में जो पन बिजली लगाने का प्रस्तावित है उसको पूरा कराया जाए । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कैमूर जिला में बिजली की व्यवस्था की जाए, सिंचाई के मामले में परिपूर्ण हो सके । इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री जगदीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आज एक पुस्तिका एसेम्बली में बंटी है, सरकारी आश्वासन की सूची का, इसमें आश्वासन संख्या पृष्ट १०८ पर देखा जाए, आश्वासन संख्या २३११/९३ वह मेरा और रामश्रय यावू का प्रश्न था, बिजली के संबंध में और जो किसानों का ट्रान्सफार्मर जल गया, जो स्थिति है कि ७५ प्रतिशत् की आपने जो बैरियर लगायी है उसे खत्म करके किसानों को आप ट्रांन्सफार्मर दीजिए । उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री लालू प्रसाद का आश्वासन है जिसे मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूं । "श्री लालू प्रसाद, महोदय, सुखाड़ को हम चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे, मुख्य सचिव को हमने कहा कि जिस इलाके का ट्रान्सफार्मर जला हुआ है, वहां के किसानों ने पैसा जमा नहीं किया तो उनको काम रूक न जाए, किसानो को पैसा क्लीयर नहीं होने पर भी हम ट्रान्सफार्मर उपलब्ध करायेंगे ।" आज तक यह लागू नहीं हुआ । आश्वासन चूंकि ऊर्जा विभाग का है, और आज डिमांड इस विभाग का है, इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री लालू प्रसाद ने जो आश्वासन दिया था, उसे पूरा कीजिए । लेकिन आपके द्वारा इसे पूरा नहीं

किया गया ।

उपाध्यक्ष : सुखाड़ की स्थिति में यह दिया गया है ।

श्री जगदीश शर्मा : वह आज तक जला हुआ है, लगा नहीं है, १९९३-९४ का है ।

श्री जगदानन्द सिंह : उस साल अलग से पैसा बिजली बोर्ड को दिया गया । सुखाड़ के वक्त ट्रान्सफार्मर बदला गया और ३५ करोड़ रूपया बिजली बोर्ड को दिया गया था । हो सकता हो, यह ट्रान्सफार्मर नहीं बदला गया हो ।

श्री जगदीश शर्मा : आश्वासन में यह है ।

उपाध्यक्ष : यह किस संदर्भ में है ?

श्री जगदीश शर्मा : सुखाड़ कार्य के लिए । उस समय सहमति हुई थी कि ट्रान्सफार्मर जो किसानों के जले हुए, उन्हें बदल देंगे ।

उपाध्यक्ष : इसे आश्वासन समिति डील कर रही है ।

श्री फुरकान अन्सारी : सरकार ने बदला नहीं ।

श्री जगदानन्द सिंह : उस समय अलग से पैसा रिलीफ से बिजली बोर्ड को दिया गया था ट्रान्सफार्मर बदलने के लिए और बदला गया था ।

उपाध्यक्ष : बिजली बोर्ड को अलग से पैसा दिया गया था, हमको भी समरण है । रिलीफ मद् में बिजली बोर्ड को अलग से पैसा दिया गया था ।

श्री जगदीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, कहीं नहीं बदला गया, हम आग्रह करेंगे कि आज जो बिजली बोर्ड का डिमान्ड है, उस चर्चा में सरकार यह घोषणा करे कि ट्रांसफार्मर लगाने का जो बैरियर है कि 75 प्रतिशत राशि का भुगतान हो जाय तब ट्रांसफार्मर लगेगा, यह बैरियर ठीक नहीं है, सरकार इस बैरियर को लो डाउन करे और ट्रांसफार्मर दे ।

श्री दुलाल भुंइया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने

के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, बिजली के लिये आज माननीय सदस्यों ने सदन में, अपने अपने सवाल और सुझाव पेश कर रहे हैं और मैं अपनी समस्याओं को आपके माध्यम से मंत्रीजी को अवगत कराना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, हमलोग झारखण्ड क्षेत्र से आते हैं और उस क्षेत्र में जो बिजली का उत्पादन होता है और हमारे तेनुघाट में जिस तरह से बिजली का उत्पादन होना चाहिये उस तरह नहीं हो रहा है । आज एक फेज में उत्पादन हो रहा है केवल 210 मेगावाट का और मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि तेनुघाट में बिजली उत्पादन की क्षमता 1540 मेगावाट है और इतना उत्पादन होना चाहिये और जो आज पूरे बिहार में बिजली की कमी है ।

उपाध्यक्ष : 1540 मेगावाट क्षमतावाले उत्पादन केन्द्र से अभी कितना मेगावाट पैदा हो रहा है ।

श्री दुलाल भुंइया : अभी 210 मेगावाट पैदा हो रहा है । यहां करीब करीब सभी युनिट बंद हो चुका है । अगर सरकार 3 फेज को चालू करे तो वहां बिजली उत्पादन की क्षमता 1540 मेगावाट हो सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, पेचेत, तेलीया और दामोदर और इस प्रकार हमारे झारखण्ड क्षेत्र में बड़ी परियोजना चलती और बिजली की ज़ो उपेक्षा, वह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वहां के गांव में अभी भी जिस तरह से बिजली की व्यवस्था होनी चाहिये सरकार की ओर से, वह नहीं हो पाई है । हमारे झारखण्ड क्षेत्र में जो छोटे छोटे उद्योग हैं, वे सारे उद्योग ठप पड़े हुये हैं और जो भी किसान उस क्षेत्र में रहते हैं और खेती करते हैं, उनको सिंचाई के लिए बिजली चाहिये मगर बिजली नहीं मिल पाती है और किसान सिंचाई से वंचित रह जाते हैं । जो लिफ्ट एरिगेशन है वह बंद पड़ा हुआ है । यह गम्भीर चिन्ता का विषय है जिस से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं ।

हमलोग उस क्षेत्र से एकदम सटे हुए हैं, सामने बंगाल है, बंगाल में जिस तरह से बिज़ली का उत्पादन होता है, गांव-गांव में बिजली लोगों को दी जाती

है, जो बिजली के कन्ज्यूमर्स हैं उनको बिजली दी जाती है । यह बंगाल के लोगों को उपलब्ध है और साथ में उड़ीसा भी है जहां लोगों को बिजली मिलती है और हमलोग इस क्षेत्र से आते हैं और वहां के सारे गांवों को बिजली नहीं मिलती है । महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह भुईयाँडीह क्षेत्र हैं । मैंने सरकार को कई बार लिखकर भी दिया है और विद्युत बोर्ड को भी लिखकर दिया है, लेकिन आज तक इस क्षेत्र की बिजली के मामले में उपेक्षा की गयी है । हमारे घर में भी अभी तक बिजली नहीं है, 25-30 साल से वहां बिजली नहीं है । महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री ज्योतिन सोरेन । आप अपनी बात को दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री ज्योतिन सोरेन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा से सम्बन्धित मांग पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचारों को रखा है और मुझे भी कुछ अनुभव है । यहां पर महोदय, सरकार की जो स्थिति हमलोग देख रहे हैं, महोदय, जो रिपोर्ट उन्होंने सामने रखा है, माननीय सदस्यों के सामने रखा है, उसमें उन्होंने जो उनकी कमजोरियां हैं, उसकी जो आलोचना होनी चाहिए, उसपर सरकार ने लीपा-पोती करके, उससे अलग हटाकर तथ्यों को सही ढंग से सदन में रखने का काम नहीं किया है । माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि जब तक हमारे बिहार में विद्युत की स्थिति नहीं सुधरती है, जब तक हम ऊर्जा के क्षेत्र में पिछड़े हुए रहते हैं, तब तक हम विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं । लेकिन सरकार उपलब्धियों के बारे में क्या कार्यक्रम अपना रही है ? इस सम्बन्ध में देखा जा रहा है कि सरकार के पास कोई कारगर कार्यक्रम नहीं है और सरकार की अभिरूचि भी इस सम्बन्ध में नहीं दिखायी देती है । महोदय, निकट भविष्य में बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार की पहल से कुछ सफलता मिलेगी, ऐसा भी दिखायी नहीं दे रहा है । महोदय, हमारी उपलब्धि ऊर्जा के क्षेत्र में ....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है । अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ बोलना हो, तो बोलें ।

श्री ज्योतिन सोरेन : महोदय, मैं कह रहा था, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा बिहार दिनोंदिन पीछे हट रहा है, गिर रहा है । तेनूघाट के सवाल को ही देखा जाय तो वहां पर 6 इकाईयों में से दो में उत्पादन शुरू हो गया था, लेकिन उन दो इकाईयों में से भी एक फिर खराब हो गयी और मात्र एक में ही विद्युत् उत्पादन हो रहा है । बाकी इकाईयों का निर्माण कब होगा, कब उनमें उत्पादन शुरू होगा, यह सरकार बता पाने की स्थिति में नहीं है । इसी तरह से बरौनी में भी कई इकाईयों खराब पड़ी हुई हैं । अगर वे ठीक होतीं तो उत्तर बिहार के लोगों को उससे बिजली मिल पाती, लेकिन वहां भी इकाईयाँ खराब पड़ी हूई हैं । महोदय, मैं अपने जिले पाकुड़ जिले की बात करता हूँ,

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

वहां 40 हजार पत्थर मजदूर काम करते हैं और वहां बिजली जब बन्द रहती है तो उद्योग काम से वंचित होना पड़ता है । इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि पाकुड़ जिला मुख्यालय या पाकुड़ जिले के किसी भी उपर्युक्त जगह चुनकर पूरे संथाल परगना इलाके के लिये अगर ग्रीड बनाकर हम कहलगांव से या फरक्का से या डी0भी0सी0 लाइन से लाइन जोड़कर उस गरीब जनता के लिए उद्योग को चालू रखने का काम हो सकता है लेकिन इस दिशा में अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ है । महोदय, ।। प्रदेश के कुछ खास समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । महोदय, हमारे पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड के नदी के किनारे दर्जनों रिभर बोरिंग है । उससे सिंचाई के लिये वहां बिजली अगर ठीक रहती तो उस इलाके में सैकड़ों एकड़ ज़मीन की सिंचाई हो सकती लेकिन बिजली की खराबी के चलते ही वहां तमाम सिंचाई अभी रूका हुआ है और किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है । हमारे महेशपुर क्षेत्र को अमलापाड़ा पावर सब स्टेशन से बिजली मिलती है लेकिन वह बहुत बड़े इलाके को वहां से विद्युत आपूर्त्ति करने का

बोझ सही तरीके से सह नहीं पाता है । अमरूपाड़ा प्रखंड के अन्तर्गत सिंघासी में वायुसेना का अड्डा है जहां पूर्वी जोन के लिये रडार बनाये गये हैं और वहां भी अमरूपाड़ा सब स्टेशन से विद्युत आपूर्त्ति होती है और उस क्षेत्र में विद्युत आपर्त्ति का काम उसी सब स्टेशन से होता है । यही कारण है कि उस इलाके के लोगों को विद्युत नहीं मिल पाती है । इसलिए हम सरकार से यह मांग करना चाहेंगे कि उस क्षेत्र लोगों को विद्युत मुहैया कराने के लिये महेशपुर में एक पावर सब स्टेशन का निर्माण करने के लिये वहां पर जगह का चयन भी किया है । महोदय, उस इलाके में विद्युत की स्थिति आज ठीक हो सकती है । हमारे यहां कोयला भी है । एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि वहां जो भी नदी नाले हैं, उसमें केवल कोयला दिखाई देता है और लोग खोद करके, माथे पर ढ़ो करके, साइकिल पर ढ़ो करके ले जाते हैं और उपयोग में ले रहे हैं लेकिन उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है. । हमारे गांव के बगल में एक चांदपुर गांव है जहां पर ड्रीलिंग का काम किया गया था पानी पीने के सवाल पर लेकिन वहां ड्रीलिंग सफल नहीं हुआ है । इसका कारण है कि वहां तांवा या निकेल जैसा पदार्थ निकला है जो हमारे पास भी कुछ है । मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे इलाके में इतनी सारी सम्पदायें हैं और ऊर्जा के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है । वहां बिजली की चोरी हो रही है । चोरी के मामले में भी हमारे इलाके में बंगाल के पुलिस ने चोर को सामान के साथ पकड़ा । वह हमारे पाकुड़ जिला के पुलिस को इनफौर्म भी किया लेकिन पाकुड़ जिला के पुलिस ने अभिरूचि नहीं ली और अधिकारियों ने भी बिजली के तार को वहां से बरामद करके, केस करके चोर को पकड़ने की दिशा में कोई काम नहीं किया ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें । माननीय ऊर्जा मंत्री.....

(व्यवधान)

बैठिये न । सरकार का उत्तर भी सुनियेगा न?

(इस अवसर पर समता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं मार्क्सवादी

समन्वय समिति के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े थे ।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सरकार का उत्तर तो सुन लीजिये । जब समान्य प्रशासन पर मांग परसों आयेगी उस दिन आपको समय दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री दिलीप वर्मा सभा के वेल में चले आये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपनी सीट पर जाकर बैठें । माननीय सदस्य सरकार का उत्तर सुन लें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया अपनी सीट पर बैठ जायं । आप सदन का समय क्यों बर्बाद करते हैं । मंत्री महोदय खड़े हैं, वे बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री जगदानन्द सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य नहीं बोल पाये हैं, हम सभी की भावनाओं का कद्र करते हैं । जो माननीय सदस्य बोले हैं, जो माननीय सदस्य नहीं बोले हैं, सभी की भावना का कद्र करता हूँ । जो बिजली की स्थिति है इस राज्य में महोदय, आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूँ । मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्य से (श्री दिलीप वर्मा) कि वे अपनी सीट पर बैठ जायं । ये बेतिया के तरफ के रहने वाले हैं, बेतिया में बिजली कहां से आयेगी, मैं बतलाऊंगा, वहां बिजली की कमी है, मैं बतलाऊंगा, ये बैठ तो जायं महोदय ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री दिलीप वर्मा अपने स्थान पर चले गये)

श्री जगदानन्द सिंह : महोदय, राज्य सरकार के एक बहुत बड़ी राशि खर्च

करना तय किया है ।

(इस अवसर पर समता पार्टी, भारत का कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी समान्वय समिति के माननीय सदस्य ने सदन का वहिष्कार किया)

श्री जगदानन्द सिंह : महोदय, राज्य सरकार इस बात को मानती है कि हमारे यहां खेती के लिये, उद्योग के लिये, व्यापार के लिये जितनी बिजली चाहिये; उनके अनुपात में कहीं न कहीं कमी है । देश के पैमाने पर अन्य राज्य जहां जाकर खड़े हैं, उसके बगल में हमें जाकर खड़ा होना है तो एक बहुत बड़ी राशि खर्च करनी पड़ेगी तब उत्पादन बढ़ेगा और उसके डिस्ट्रीव्यूशन के आवश्यक उपाय करने पड़ेंगे ।

इनलोगों को बिजली से क्या मतलब है ? हमने महोदय एक भी बात को छिपाया नहीं है । माननीय सदस्य अलोचना के जिस स्तर पर गये हैं उससे भी आगे जाकर राज्य में जो विद्युत की स्थिति है, उत्पादन का, संचरण का और वितरण का मैंने सबका स्पष्ट चित्रण किया है । वर्षो वर्ष से ही नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत में बिहार की उपेक्षा बिजली के क्षेत्र में की गयी है । लोग जानते हैं कि यहां अबार्दी देश का दस प्रतिशत है और जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इस राज्य में बिजली के परिक्षेत्र में वह २.०५ प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ है । आप समझ लीजिये २.०५ प्रतिशत इन्वेस्टमेंट ओर आबादी दस प्रतिशत । मतलब स्पष्ट है कि जो यहां पूंजी निवेदन होना चाहिये था योजना के द्वारा सेंटर सेक्टर में और स्टेट सेक्टर में वह नहीं हो पाया है । बल्कि स्पष्ट मैंने कहा कि राष्ट्रीय औसत पर जहां ३२५ युनिट प्रतिव्यक्ति खपत है हमारे यहां प्रतिव्यक्ति खपत १२५ युनिट है । लेकिन इस स्थिति में भी हम यह कहकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं क्योंकि इस विश्लेषण में मैं नहीं जानना चाहता कि किनकी गलती और कितनी गलती नहीं थी और किनके बदौलत ये चीजें आई तो इस राज्य का भला नहीं होने वाला है । लेकिन राज्य की जनता जानना चाहेगी, राज्य की आबादी जानना चाहेगी, माननीय सदस्य जानना चाहेंगे कि सरकार क्या कर रही है ? महोदय, पहली बार एक लंबी छलांग लगाने के लिये सरकार तत्पर है ।

माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में । महोदय ट्रांसमिशन और मेन्टीनेंस में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हैं । मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आज के दिन जितना भी हमारा कनेक्टेड लोड है यदि हमारा संरचन व्यवस्था ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक हो जाय तो २४ घंटे बिजली देने के लिये हर व्यक्ति को हमारे पास बिजली उपलब्ध है । महोदय, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कभी कभी मजाक किया जाता और एक बार अखबार में लिख दिया कि- "नयी खोज" । मा0 मंत्री ने कहा कि पावर का फल्डींग है । मैं पुनः कह रहा हूं कि पूरे देश के पैमाने पर दूसरे राजयों के पैमाने पर और भारत सरकार चाहती है कि बिजली के फल्ड को अपनी तरफ ले जाय । महोदय, मैं आपको सूचना दूं कि हमारी संरचन और वितरण व्यवस्था ठीक रहती तो दो सौ मेगावाट बिजली बाहर नहीं चली जाती । २०० मेगावाट बिजली बाहर जाती है जो हमारी बिजली है । मेरी मान्यता है, सरकार की मान्यता है कि बिका हुआ सोना बापस हो सकता है लेकिन एक बार बिजली राज्य के बाहर चली गयी तो बापस नहीं लायी जा सकती है । महोदय, बिजली इतनी कीमती चीज है और बिजली राज्य के बाहर जा रही है । उत्तर बिहार का डिमांड है आज के दिन में ३०० मेगावाट लेकिन मुजफ्फरपुर और बरौनी में जब समस्या होती है तो किसी तरह पूर्णिया की तरफ से १२५-१५० मेगावाट बिजली लाते हैं और किसी तरह मुजफ्फरपुर और बरौनी में समस्या हो गयी तो चाहकर भी उत्तर बिहार में बिजली नहीं दे पाते । ३०० मेगावाट बिलकुल सप्रेस्ड डिमांड है । अतः बिजली सही ढंग से मिलने लगे और सच है कि कृषि के लिये जो वहां पर पोटेंशियलीटी है सच है उत्तर बिहार में बिजली आज के दिन एक हजार मेगावाट देना चाहिये लेकिन उतनी बिजली हम नहीं दे सकते हैं । महोदय, एक गंगा का क्रासिंग बना था आज से कुछ साल पहले वह खराब हो गया । और एक केवल क्रासिंग था मोकामा में वह ध्वस्त हो गया । हमलोग चाहते थे कि बिहारशरीफ-बेगुसराय को जोड़ दें । बिहारशरीफ-बेगुसराय एक तरफ से २०० मेगावाट बिजली हम पंप करें उत्तर बिहार में । महोदय, माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि जो पावर ग्रीड कौरपोरेशन को हमलोगों ने काम देने का निर्णय किया है और उसने वादा किया है कि ७-८ महीनें में वह काम करेगा । लेकिन महोदय, कुछ

झगड़ा कुछ झंझट कुछ विवाद जो हमलोगों के यहां कभी कभी हो जाता है उसके चलते भी लाइन नहीं बना पाये । लेकिन उसका कुछ पीलर लगाने हैं । ट्रांसमीशन लाइन लगाना है । पावर ग्रीड कौरपोरेशन कह रहा है कि बिजली बोर्ड के मान्य शर्त्तों पर इस काम को करेंगे और इसके लिये १०० करोड़ रु0, महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं जो रु0 आठ साल में खर्य नहीं हुआ उससे एक मुश्त अधिक इस साल हम ट्रांसमिशन लाइन में खर्च करने जा रहे हैं । मैं आपको बताउंगा कि इस ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन सी लाइन हम बनायेंगे। पूर्णिया से लेकर बेगुसराय तक । फिर एक ट्रांसमिशन लाइन लगाने जा रहे हैं बेगुसराय से हम उस इलाके में बिजली नहीं ले जा सकते और समस्तीपुर की बातें कही जाती है कि जो हमारा उधर का इलाका है मोतीहारी बेतिया से लेकर सीतामढ़ी से लेकर दरभंगा का इलाका हम बेगुसराय से समस्तीपुर ट्रांसमिशन लाइन लगायेंगे और जिसके चलते १००-से १५० मेगावाट बिजली ले जायेंगे । और हम पटना को आरा से जोड़ेंगे क्योंकि आरा के माननीय सदस्य कहते हैं कि पटना में बिजली रहती है और हमारे यहां आरा में नहीं रहती । कभी कभी उस लाइन में बिजली फेल हो जाती है बोधगया से पटना तो फतुहा से बिहार शरीफ से लानी पड़ती है तो कई समस्या जटिल हो जाती है । एक अल्टरनेटिव लाइन और होगा । इस तरह से एक बड़ा पूंजी निवेदन हम ट्रांसमिशन लाइन में लगाने जा रहे हैं और यह ट्रांसमिशन लाइन तैयार हो जायेगी तो हम २०० से ३०० मेगावाट बिजली खपत कर सकेंगे ।

(व्यवधान)

महोदय, यह स्तर है हमलोगों के बहस का, देख लीजिये . बिहार हमारा घर है एक किनारे से बात करते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं है । कहीं से शुरू होकर कहीं जाकर अंत होगा । मैं कहना चाहता हूं कि दक्षिण बिहार में हमारी ट्रांसमिशन लाइन की कमी नहीं है बल्कि हमारे ग्रीड की क्षमता कम है । हम अनेकों ग्रीड बनाने जा रहे हैं । एक एक नाम लेकर बताउंगा कि हम इस बार कितना ग्रीड जो हमारा २२०, १३२, ३३ हजार का ग्रीड हम कितना बनाने जा रहे हैं । मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा अधूरा ग्रीड आपके दिमाग में जितना

है एक साल के अंदर या कुछ अधिक समय में यदि पैसे की कमी हुयी या किसी अन्य कारण से कोई कमजोरी रही तो एक साल से कुछ अधिक समय में लगायेगी । मैं आश्वासन देना चाहता हूं इस सदन को कि यह सदकार ट्रांसमिशन लाइन लगायेगी । महोदय, यह सच है कि वर्षो की गलती का यह परिणाम है यदि सारी प्लानिंग ठीक हुयी होती तो उत्पादित बिजली की कमी इस राज्य में किसी तरह नहीं होती । डिस्ट्रीव्युशन साइड में और भी कमी है।

महोदय, माननीय सदस्य, श्री जवाहीर प्रसाद जी कुछ बोलने के लिये माइक ठोक कर रहे हैं । इनके इलाके में बिजली की परेशनी है मैं जानता हूं। मैं एक एक चीज को कहूंगा तो समय लगेगा । लेकिन ७८ पावर सब स्टेशन डिफरेंट जोन में हम लगाने जा रहे हैं आप कहेंगे तो जोन बाइज हम बता देंगे कि किस जोन में कितना सब स्टेशन बनाने जा रहे हैं । महोदय, ७८ सब स्टेशन और लगायेंगे और अनेकों ग्रीड स्टेशन और अनेकों ट्रांसमिशन लाइन इस वर्ष हमारी लगेंगी । रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन के अंतर्गत जो जो सब स्टेशन आयेंगे उस पर १२५ करोड़ रु0 हमलोगों ने बजट में रखा है । महोदय, यह कोई साधारण पैसा नहीं है । जो उत्पादन है वह हमारा अपना होगा । यह सच है कि हमारा उत्पादन पी0एल0एफ0 १५ प्रतिशत है । जिसमें दिनों दिन ह्रास होता रहा है । क्योंकि आवश्यकता से कम हमारा पावर स्टेशन रहने के चलते हमारा कितना लोड बढ़ता और जो हमारा स्टेचुटरी कैपिटल मेन्टीनेंस नहीं हुआ पैसे के अभाव में इतनी बिजली की कमी इसीलिये हुयी है । आवश्यकता के अनुसार लोड के चलते पी0एल0एफ0 घटते घटते १५ पर चला गया है । हम १५० करोड़ रु0 पावर फाइनेंस कौरपोरेशन से बिहार सरकार के काउंटर गारंटी से बिजली बोर्ड को लोन दिलाने जा रहे हैं और इस १५ प्रतिशत पी0एल0एफ0 को ७ प्रतिशत पी0एल0एफ0 पर ले जायेंगे और ४ गुणा बिजली का उत्पादन अपने श्रोत से करेंगे । तेनुघाट में आटोमेटिक सिस्टम् है । महोदय, अफसोस की बात है कि जो उत्पादन क्षमता है उसको उससे उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रतिदिन ५०० मेगावाट हमारे सिस्टम में रहता है । ५०० मेगावाट अधिक रहने के चलते नतीजा है कि दो से ढाई फ्रिक्वेंसी अधिक रहती है । हमारे

बिजली घर को ५०, साढ़े पचास फ्रिक्वेंसी पर चलना चाहिये लेकिन कभी कभी यह साढ़े बावन-तिरपन फ्रिक्वेंसी हो जाती है । तेनुघाट में अटोमोटिक सिस्टम है जहां साढ़े बावन से अधिक फ्रिक्वेंसी होने पर एकाएक आ टोमेटिक ट्रीप कर जाता है । अधिक फ्रिक्वेंसी पर सप्लाई पावर स्टेशन या बिजली घर सदा के लिये कौलैप्स हो जायेगा । एक्सेस फ्रीक्वेंसी में पावर स्टेशन आवश्यक है, जिसके लिये मैं कहता हूँ कि कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा । बिजली स्टोर नहीं होती है कहीं । जितना बनेगा, खर्च करना पड़ेगा । खर्च में कमी आयेगी, हमारा स्टेशन खराब हो जायेगा, खर्च अधिक होगा तो ओवरलोडिंग में चला जायेगा स्टेशन ।

महोदय, एक लम्बी छलांग लगाने के लिये तैयार हैं । यह सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड से, स्पेशल प्लान से दे रहे हैं । अफसोस के साथ फिर मुझे कहना पड़ता है, भारत सरकार का कोई एक पैसा बाकी होता है, तुरंत हमारे प्लान असस्टिंस से काट लेती है । माननीय सदस्यगण, कई बार इसपर आप प्रश्न करते हैं कि प्लान कैसे कटौती हो जाती है । भारत सरकार हमारे प्लान असस्टिंस से काट लेती है । एक तरफ यह है, दूसरी तरफ आप देखिये कि भारत सरकार हमारा कितना पैसा बाकी रखती है, आप भी जानना चाहेंगे ।

महोदय, अफसोस की बात है । हम उनका पैसा नहीं काट सकते हैं । हमें उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है । यदि हमारा यह पैसा नहीं काट सकते हैं । हमें काम होता । आप देखिये- एच0ई0सी0, रांची के पास 1,53,26,04,017 बकाया है, एच0एफ0सी0, बरौनी के पास 96,23,01,160 रु0 बकाया है, एन0टी0सी0 मोकामा के पास 91,05,011 रूपये, गया कॉटन ऐंड जूट मिल्स के पास 1,01,240 रु0, भारत वैगन ऐंड इंजीनियरिंग, मोकामा के पास 68,84,519 रु0 भारत वैगन ऐंड इंजीनियरिंग, मुजफ्फरपुर के पास 1,12,826 रु0, कुमारध्वी मेटल कास्टिंग, धनवाद के पास 21,20,06,720 रु0 और आई0डी0पी0एल0, मुजफ्फरपुर के पास 2,48,29,964 रूपये बकाया है । कुल मिला कर इन उपक्रमों पर 2,74,79,45,459 रूपये बकाया है ।

महोदय, हम जब उनसे भी मांगते हैं तो पैसा नहीं देते हैं, जबकि इतने हमारे उनके ऊपर बकाया हैं । उससे भी बड़ी चीज देखें महोदय । सी0सी0एल0 पर हमारा बकाया है 164.25 करोड़, वी0सी0सी0एल0 पर 1092.61 करोड़ और ई0सी0एल0 पर 201.86 करोड़ है । कुल मिला कर इन तीनों पर 1458.72 करोड़ का बकाया है हमारा ।

महोदय, भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों पर 2,74,79,45,459 रूपये का बकाया और ये जो तीनों कोल कम्पनियां हैं इन पर 1458.72 करोड़ रूपये। इस तरह से सब मिला कर भारत सरकार पर हमारा बकाया है 17,33,51,45,459 रूपये ।

अध्यक्ष महोदय, आपको पता है अगर हमारे पास ये 1773 करोड़ रूपये रहते तो हम 500 मेगावाट बिजली बनाते । उसके लिये स्टेशन बनाते ।

श्री उपेन्द्र नाथ दास : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बता दें कि ये रूपये केन्द्र सरकार के इन संस्थानों पर कब से बकाया हैं ?

श्री जगदानंद सिंह : महोदय, मैं फिर कह रहा हूँ, 1989 से लेकर और उसके कुछ पूर्व से आज तक बकाया है ।

महोदय, मैंने एक बार कहा था माननीय सदस्य, किसने कमी की, इस पर बहस में जायेंगे तो आज की कमी को दूर नहीं कर पायेंगे । मैं फिर जानकारी दे रहा हूँ, सिर्फ सुनने के लिये नहीं, आप यहां के विपक्ष हैं, वहां के सत्ता पक्ष हैं आपका सहयोग अगर इस पर मिल जायेगा, आपका हम नाम लेंगे। हमारा बकाया दिलवा देंगे आप तो हम 5-6 सौ मेगावाट बिजली पैदा करने का स्टेशन खड़ा कर लेंगे । शिकायत होगी इससे आपकी क्या ? क्या इस राज्य में अधिक बिजली मिल जायेगी तो किसी की शिकायत होगी ? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है । आज से 15 दिन पहले जो हमारा ईस्टर्न ग्रिड है, उसने कहा हम नदर्न ग्रिड को, वेस्टर्न ग्रिड को अपने सिस्टम से बिजली देना चाहते हैं । हमारे आफिसरों ने कहा यह संभव नहीं है । हमने कहा नहीं, मुल्क एक है । मेरे यहां फ्लडेड है और उनके यहां स्कार्सिटी है, 100 मेगावाट बिजली ले

जाने के लिये इंतजाम किया । यहां फालतू बिजली है और वहां बिजली की जरूरत है । ऐसा नही करने से राष्ट्रीय उत्पादन में कमी होगी और अंत में हम सबको फल भुगतना पड़ेगा । हमने यह नहीं देखा कि वहां कौन सी सरकार है। सरकार होती है प्रशासन करने के लिये । यह सर्वसत्य नहीं है । सर्वसत्य है आबादी और उसकी समस्या । उस आबादी की सर्वसत्य समस्या को हल करना पड़ता है । यह मैं उपेन्द्र नाथ दास जी को कहना चाहता हूँ, बिजली बोर्ड का, पूरे राज्य पर करीब-करीब 1800 करोड़ रूपये से अधिक बकाया है ।

महोदय, बिजली बोर्ड का सारा पैसा मिले तो हमको कंसोलिडेटेड फंड से इतना पैसा नहीं देना पड़ता ।

श्री फुरकान अंसारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ इनफौरमेशन पर खड़ा हूँ । मंत्री जी, जब केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठान पर 1700 करोड़ बकाया है तो आप क्यों उनको छोड़े हुए हैं, आपका इनसट्रक्सशन जाना चाहिए, लाइन काटने के लिए आप लाइन काटने में असमर्थ हैं क्या ?

श्री जगदानन्द सिंह : महोदय, एक चीज मैं सदन को एवं माननीय सदस्य को बता दूं कि कोलवरी का लाइन काट नहीं सकते हैं, यह कनटिन्यू प्रॉसेस है, उसको लाइन देना है, अगर लाइन काट देते हैं तो हजारों-हजार मजदूर मर जायेंगे । उसी तरह से महोदय रेल बिजली से चल रही है, अगर हम रेलवे को बिजली का लाइन काट दें तो हजारों हजार गॉड़ियाँ वहीं की वहीं खड़ी रह जायेंगी और लाखों-लाख यात्रियों को कठिनाईयाँ आयेगी । महोदय, हमारी सरकार इसके खिलाफ है, हमारी सरकार राष्ट्र के खिलाफ नहीं है । ऐसी ही बहुत सी बातें हैं जिसके कारण हम लाइन नहीं काट सकते हैं ।

(व्यवधान)

महोदय, मुझे 20 मिनट का समय बोलने के लिए मिला है, इतना कम समय में मुझे अनेकों बात बताना है । महोदय, एक बात और कहकर मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ । महोदय, हमारे राज्य का सबसे बड़ा बकाया इन्डस्ट्रीयल कनेक्शन पर है, ये बड़े-बड़े लोग हैं । महोदय, आज के दिन इनपर 936 करोड़ रूपया

बकायां है, अगर ये पैसे का भुगतान कर देते तो जो गरीबों को एक बल्व देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है, लेकिन इन अमीरों के पास करोड़ों करोड़ रूपया बाकी रह जाता है । अगर सरकार उनपर कार्रवाई करती है तो ये अमीर लोग यहाँ से लेकर कोर्ट कचहरी, छोटा से लेकर बड़ी कचहरी तक पैसे का भुगतान नहीं करना पड़े, उसके लिए चले जाते हैं । अगर महोदय, ये अमीर लोग सरकार को बकाया पैसा दे दें तो आज गरीबों के हजारों गावों को हम विद्युतीकृत कर सकते हैं । महोदय, बहुत से माननीय सदस्य आर0ई0सी0 की चर्चा कर रहे थे । महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि इस साल चार हजार गॉव, जिसकी चर्चा आपलोग भी करते हैं, आर0ई0सी0 से पोल लगा, तार लगा या कागज पर कर दिया, सरकार के पास ऐसे गॉवों की सूचि है । महोदय, 32 हजार गॉवों में बिजली देने की बात है, लेकिन 32 हजार में 10 हजार गॉव की समस्या है, वहाँ बिजली नहीं है, ट्रान्सफर्मर नहीं है, तार नहीं होने के कारण लगे ही नहीं होगें, अगर वहाँ लगे भी होगें तो चोरों ने उसे काट लिया होगा। महोदय, एक बात मैं सदन को और बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि बिजली साधारण चीज नहीं है, जैसे खून की धमनियाँ विकास कीं धमनियाँ है, यदि हम उसको काटते हैं तो हमारा जीवन नष्ट हो जायेगा, ठीक उसी तरह से यदि बिजली का तार को काट दिया जाय तो बिजली सदा के लिए बंद हो जायेगी । महोदय, इसमें सभी का सहयोग चाहिए, जिस तरह से महोदय हम अपने खेत खलिहान की रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह हमें चोरों से भी उसकी रक्षा करनी होगी और उसके लिए महोदय आप सभी लोगों से सहयोग की जरूरत है । महोदय, हमारे पदाधिकारी भी काम करेंगे । महोदय, जिन इलाकों में आपलोगों का सहयोग मिल रहा है, उन इलाकों में अच्छी बिजली मिल रही है, जहाँ-जहाँ जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है, वहाँ-वहाँ भी अच्छी बिजली मिल रही है, इसलिए हम सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि इसमें सहयोग आपका मिले । महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस साल तीस हजार गॉवों का पुनर्वास विद्युतीकरण करेंगे, 1200 नये गॉव में बिजली भी देंगे, कम से कम डेढ़ हजार हरिजन बस्ती को भी हम बिजली देंगे, इसके लिए 10 करोड़ रु0 का प्रावधान भी रखा है ।

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, इस बात को क्लीरिफाई कर दें । पूर्व उर्जा मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी बोल रहे थे कि यह सरकार सत्य पर असत्य और असत्य पर सत्य कहना बंद करें । तब ये बतायें कि फिर ये बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं, क्या यह सत्य पर असत्य की बात है या और कुछ बात है ।

(व्यवधान)

श्री जगदानन्द सिंह : महोदय, हो सकता है इसमें कुछ असत्य निकल जाय, लेकिन उतना असत्य नहीं होगा कि 10 हजार गाँवों की हम बात करें और एक में भी बिजली नहीं पहुँच पाये, इतना असत्य नहीं होगा । महोदय, जैसा कि विजेन्द्र जी ने कहा कि सरकार ने घोषणा की थी कि हम 10 हजार गाँवों में बिजली देंगे, लेकिन हमने नहीं दिया, तो मैं माननीय सदस्य श्री विजेन्द्र जी को बताना चाहता हूँ कि हम 10 हजार गाँवों में बिजली पहुँचा देते, लेकिन भारत सरकार ने हमारे प्लान का जो पैसा था, उसको भारत सरकार ने बकिऔटा में काट लिया ।

इसलिए पेरशानी तो होती है ।

(व्यवधान)

श्री जगदानन्द सिंह : महोदय, मैं एक सूचना दूं कि सारी विपत्तियों और परेशानियों के बावजूद भी, जब हमलोग वर्ष 1990-91 में आए थे, उस समय कुल मिलाकर सात हजार मिलियन यूनिट हम साल भर में देते थे और आज विभिन्न श्रोतों से 10 हजार मिलियन यूनिट वार्षिक खपत कर रहे हैं यानि 50 फीसदी खपत बढ़ी है । हमारा उत्पादन भले ही घटा हो लेकिन तेनुघाट और एन0टी0पी0सी0 से इसकी पूर्त्ति करते हैं । इस वर्ष 50 फीसदी बिजली बढ़ी है। फिर भी हम संतुष्ट नहीं है । आज जहां हिन्दुस्तान में 300 यूनिट प्रति व्यक्ति की जरूरत है, वहीं हम 100 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली मुहैया करा रहे हैं ।

एक साल के भीतर हमारा ट्रांसमीशन लाईन और डिस्ट्रीब्यूशन लाईन ठीक हो जायेगा तो हमारा बिजली का उत्पादन एक सौ से बढ़कर दो सौ यूनिट हो जायेगा । हमारे पास बिजली की कमी नहीं है, खपत में कमी है जिसका कारण हमने बजट में दिया है ।

महोदय, हम जो बजट पेश कर रहे हैं, जो बजट देंगे, उसमें रखा है । यह घोषणा कोई आंकड़े पर नहीं है बल्कि सत्य पर आधारित है । इसमें दो बात नहीं हैं । हमारे माननीया मुख्यमंत्री ने बड़ी परेशानी और मुस्तैदी से आदेश दिया है कि हर ताकत लगाकर, बिजली के क्षेत्र में, जो काम अच्छा हो, चाहे ट्रांसमीटर लाईन को ठीक कर, चाहे जेनेरेटर सिस्टम को ठीक कर, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाईन को ठीक कर, बिजली की आपूर्ति करने का काम किया जाये । हम गांव का विद्युतीकरण कर तथा हर क्षेत्र में लम्बी छलांग लगाने वाले हैं । यह बिहारवासियों के लिए गौरव की बात होगी जो कभी नहीं हुआ और यह इस साल होगा । अगली बार जब हम आपके सामने आयेंगे तो अधिक बिजली के साथ आयेंगे । इस कमी को हम समाप्त करेंगें ।

इसलिए मैं माननीय सदस्य श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह से आग्रह करता हूँ कि बिहार का गौरव बढ़ाने के लिए आप कटौती प्रस्ताव को वापस लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे ।

(इस अवसर पर विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया)

अध्यक्ष : अभी माननीय सदस्य सदन में नहीं हैं, इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"इस शीर्षक की मांग 10 रूपए से घटाई जाये ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । कटौती प्रस्ताव नामंजूर हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रश्न को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"ऊर्जा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 4,38,27,86,000/- (चार अरब, अड़तीस करोड़, सताईस लाख, छियासी हजार) रूपए से अनधिक राशि प्रदान की जाये ।"

(यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्षीय नियमन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण । माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 1998 को सेकेन्ड्री, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या- 4575 दिनांक 29 अक्टूबर, 97 सदन के पटल पर रखा गया था । माननीय सदस्य श्री अम्बिका प्रसाद एवं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 1998 को नियमापत्ति उठाई गयी थी । मैंने इस संबंध में नियमन देने के लिए कहा था । इस संबंध में स्थिति निम्न प्रकार हैं:-

"बिहार अराजकीय माध्यमिक विधालय (प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1981 की धारा 15 के अधीन माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उक्त अधिसूचना सदन के पटल पर दिनांक 10 जुलाई, 1998 को रखा गया था, जो अधिनियम के प्रावधान के तहत 14 दिनों तक के लिए सदन के पटल पर रखा हुआ है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 1998 का उक्त अधिसूचना सदन के पटल पर रखे जाने के बाद ही माननीय सदस्यों के बीच वितरित किया गया था ।